Nurses in Batra Hospital, which is a multi-speciality hospital, have been on strike for about a week now. The management is not prepared to listen to their genuine grievances. Consequently, patients are also suffering. The Union Government has a responsibility in the matter.

I urge upon the Minister of Health and Family Welfare to intervene immediately to resolve the strike and mitigate the grievances of the striking nurses.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

Mass graves found in Kashmir Valley

SHRI MOHAMMAD SHAFI (Jammu and Kashmir): Sir, International People's Tribunal on Human Rights in its report titled 'Buried Evidence' made public on 2nd December, 2009 in Srinagar, has stated that 2700 graves have been detected in the northern districts of Baramulla, Kupwara and Bandipora in Kashmir Valley burying around 3000 persons. The said report has, besides giving details about parents of disappeared persons, also shown pictures of these graves. During the press conference, the authors of the report stated that during the last 20 years thousands of young men disappeared and thousands have been killed in fake encounters. This issue has been agitating the minds of general public, causing alienation and discontent. Till date no response has come from the Union of India about this serious issue. This is causing a lot of resentment among the public and image of the country is likely to suffer damage in the international community. As such, an urgent response in this matter from the Government of India is prayed for.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-one minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at fifty-four minutes past one of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

GOVERNMENT BILLS

The Appropriation (No. 4) Bill, 2009

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prakash Javadekar to continue on the Appropriation (No.4) Bill, 2009. Your party is left with 25 minutes.

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, जिस तरह से कल मैंने शुरू किया, मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करूंगा कि हम वित्तीय व्यवस्थापन, financial management of the country की चर्चा कर रहे थे कि यह कैसे चल रहा है, जहां वित्तीय घाटा 6.8 है और खुद वित्त मंत्री जी ने कल पूरक मांगे रखते समय कहा कि 6.8 का घाटा रहेगा। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि यह घाटा आठ परसेंट से कम नहीं होगा। un-budgeted खर्चे और बढ़ेंगे और वह दो परसेंट बोझ और बढ़ेगा। जो स्टेट का घाटा है, वह अगर पकड़ेंगे, तो लगभग वित्तीय घाटा 14 परसेंट का हो जाता है।

2.00 P.M.

यह बहुत खतरनाक चीज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंदी के दौर में यह घाटा भी ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी वे यही कहेंगे कि घाटा ठीक है? अगर घाटा ठीक होता तो हमने FRBM कानून क्यों बनाया होता कि जिसके तहत यह कहा जाता था कि चार परसेंट से अधिक वित्तीय घाटा नहीं होगा और कम करते जाएंगे? यह वित्तीय घाटा आपकी इस वित्तीय व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। आने वाले दिनों में संकट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इसकी मैं पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं। आज जो महंगाई बढ़ रही है और लोगों को पीस रही है, उसका भी एक कारण इस वित्तीय व्यवस्थापन की असफलता, विफलता का यह प्रमाण है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। यह कोई आसमानी संकट नहीं है, यह सुल्तानी संकट है और उस सुल्तान का नाम, जैसा कि मैंने परसों भी बताया था कि यू.पी.ए. सरकार है और यू.पी.ए. सरकार की वित्तीय नीतियां हैं, जिसके कारण यह हो रहा है। इन्होंने क्या-क्या किया है, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने 2004 में सत्ता में आते ही किसानों से खरीद की मोहलत बड़ी-बड़ी कंपनियों, कारगिल, मोंसेंटो, रिलायंस, अदानी जैसी कंपनियों को दे दी। वे कंपनियां खरीद करती हैं और भंडारण करती हैं। यह मिलियन टन्स का कारोबार है। उसके कारण सरकार के गोदाम में कमी रही और सरकार गरीब को पैंतीस किलो अनाज देने का वादा भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए गरीब भी बाजार में आए। इनकी जो आयात-निर्यात नीति है, वह ऐसी है, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, मैं केवल दो आंकड़े उनके लिए बताऊंगा कि चीनी का भंडार बहुत लबालब भरा है, ऐसा आपके कृषि मंत्री कह रहे थे। उन्होंने चीनी का निर्यात नौ महीने पहले किया। 48 लाख टन चीनी इस देश से 12 रुपए की दर से निर्यात हुई। यह नोट करने की बात है कि 48 लाख टन चीनी 12 रुपए की दर से निर्यात हुई और आज 70 लाख टन 30 रुपए की दर से आयात हो रही है। क्या वित्तीय व्यवस्थापन है? क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? अगर इस तरह से व्यवहार करोगे तो महंगाई भी होगी और वित्तीय घाटा भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं, मैंने परसों भी सवाल पूछा था, वित्त मंत्री जी मुझे जवाब देंगे कि आज जो हमें चालीस रुपए में चीनी मिल रही है, वह पिछले साल की बनी हुई चीनी है, इस साल की आनी अभी बाकी है, पिछले साल की चीनी का किसान को क्या दाम मिला था? सोलह रुपए मिला था। अगर उसको सोलह रुपए मिले थे, तो बाजार में हमें पच्चीस रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन आज वह चीज चालीस रुपए में मिल रही है, यह पंद्रह रुपए बीच में कहां बढ़े और किसने खाए? इस पर किसका नियंत्रण है? यह चीज दिखाती है कि आपका सरकारी वित्त पर नियंत्रण नहीं है और बाजार पर भी नियंत्रण नहीं है। दाल और तेल का आयात किया गया, लेकिन दाल और तेल का आयात करते समय वह बंदरगाह पर सड़ रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, यह आपका व्यवस्थापन है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरक मांग में पैसा मांगते कि हम सब्सिडी देना चाहते हैं, गरीब को महंगाई से राहत देना चाहते हैं और उसको हर महीने पांच किलो दाल, पांच किलो तेल, पांच किलो शक्कर, दस, पंद्रह किलो गेहूं और दस, पंद्रह किलो चावल कम रेट पर मुहैया कराएंगे, सब्सिडाइज रेट पर कराएंगे, अगर आप इस सब्सिडी के लिए पूरक मांग रखते, तो हम उसका समर्थन कर सकते थे, क्योंकि वह ठीक होता। यह जो महंगाई है, इस महंगाई को काबू करने में आपकी वित्तीय नीति पूरी तरह से विफल रही और यह आपकी वित्तीय नीति की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, इसलिए मैं इसे आज फिर से दोहराना चाहता हूं। यह मंदी का दौर है। मंदी से आप कैसे निपट रहे हैं। वित्त मंत्री जी, आपको पता है कि मंदी के time में आपने बहुत सारे incentives दिए, लेकिन किसको incentives दिए? ये आपने उद्योगपतियों को दिए, उद्योगों को दिए। जो चालीस लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, उन चालीस लाख मजदूरों को आपने क्या सहायता दी, मैं यह पूछना चाहता हूं?

आपने उन गरीब मजदूरों को एक पैसे की भी सहायता नहीं की, जिनके जॉब्स गए, जिनकी नौकरियाँ गईं, जिनका काम चला गया, जो बेरोजगार हो गए। जो लोग एक-डेढ़ साल बेरोजगारी में रहे, उनको आपका एक पैसा भी नहीं मिला। अगर आप इसके लिए पूरक मांग रखते, तो हम इसका समर्थन कर सकते थे। कैसा है यह वित्तीय व्यवस्थापन?

आपने नारा "गरीबी हटाओ" का दिया। बहुत पहले दिया, 30-40 साल हो गए, लेकिन आज गरीब की क्या स्थिति है? आपके ही आँकड़े बता रहा हूँ। योजना आयोग कहती है कि देश में 28 फीसदी गरीबी है; तेंदुलकर, जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं, तेंदुलकर समिति का सर्वेक्षण है कि यह 40 फीसदी है; ग्रामीण मंत्रालय की सक्सेना समिति ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे 50 फीसदी लोग रह रहे हैं; NSSO के सर्वेक्षण में कहा गया है कि 60 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और आपकी सेनगुप्त कमेटी ने कहा कि 20 रुपए से नीचे कमाने वाले 70 फीसदी लोग हैं। इसलिए गरीबी रेखा के बारे में स्थिति बद से बदतर हो रही है और गरीबों की तादाद बढ़ रही है। यह आपकी वित्तीय संचालन, वित्तीय नीति की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने पूरक मांगों में 135 करोड़ मांगा है कि गरीबी रेखा का एक नया सर्वे करेंगे। नए आँकड़े आएंगे, लेकिन आप यह कब बताएंगे कि गरीबी कब खत्म होगी, लोग गरीबी से बाहर कैसे आएंगे? उनको empower करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन-सी वित्तीय नीति अपना रहे हैं, इसका कोई खुलासा आपने नहीं किया है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है?

दो बड़ी बातें हैं। एक है infrastructure. Infrastructure का मसला है देश की तरक्की से और देश की तरक्की का मापदण्ड होता है आपका सफल वित्तीय संचालन। लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है? मैं केवल बिजली की बात करूँ, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में पॉवर सेक्टर में आपने 78 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा है। अगर पाँच साल में 78 हजार मेगावाट तैयार करना है, तो हर साल 16 हजार मेगावाट होना चाहिए। सीधा हिसाब है। 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 40 हजार मेगावाट तक जाना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 12 हजार मेगावाट हुआ और 19 हजार मेगावाट का target रखा गया था। कैसे पूरा होगा 78 हजार मेगावाट का लक्ष्य? जब हमने पॉवर मिनिस्ट्री की Consultative Committee में पूछा कि क्या दिक्कत है, तो एक दिक्कत बताई गई, वित्त मंत्री सुन लें, कि पॉवर सेक्टर के reform और पॉवर सेक्टर में बिजली की generation बढ़ाने के लिए निधि की उपलब्धता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की कमी है। अगर infrastructure[] के लिए पैसे की कमी है, तो आपका क्या वित्तीय संचालन है? अगर वित्तीय व्यवस्थापन ठीक होता, तो infrastructure के लिए पैसे की कमी नहीं होती। हमने infrastructure bond निकाले थे, हमने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन अगर वित्तीय व्यवस्थापन ठीक होता, तो यह पॉवर सेक्टर आज पैसे के कारण hungry नहीं रहता।

आपने एक दूसरा नारा दिया था कि हर रोज 22 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या प्रत्यक्ष वास्तविकता है? स्थिति ऐसी बदतर है कि 22 किलोमीटर नहीं हो रहा है, हमारे समय जो 11 किलोमीटर का average था, वह 4 किलोमीटर पर आ गया। इसलिए उसमें भी कमी है। अनेक सेक्टर्स हैं, जहाँ bidding के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। कभी-कभी public investment करनी पड़ती है। मंदी के दौर में जब आप public investment करके infrastructure का निर्माण करेंगे, तो वह सुविधा केवल आने वाले समय के लिए नहीं होगी, आप मंदी से भी निबट जाएंगे और उससे ज्यादा काम होगा कि ये सड़कें बनेंगी और infrastructure development से ही देश की तरक्की होगी। लेकिन यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है, जहाँ infrastructure के लिए ही पैसा नहीं है!

आपने disinvestment की बात कही है, कितने proceeds आएंगे, यह बताया है। लेकिन आपने commit किया था कि disinvestment से, विनिवेश से जो पैसा आएगा, वह शिक्षा और health care में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है? वह तो general pool में जा रहा है। यह आपका वित्तीय घाटा कम करने के लिए जा रहा है। मैंने कहीं उसका कोई अलग से earmarking तो देखा नहीं, न उसका अलग एकाउंट है, न कुछ काम है।

यह कैसा व्यवस्थापन है कि एक तरफ आप विनिवेश भी कर रहे हो, लेकिन उसकी बेसिक ऐफिशिएंसी बढ़ाने की बात भी नहीं कर रहे हो। जो पैसा आ रहा है, वह जनरल पूल में जा रहा है, इसका क्या मतलब

हुआ? एक तरफ Fiscal Management की विफलता है, फिर supply constraints है, लेकिन मेरा उससे भी बड़ा चार्ज यह है कि you have stopped reforms. सुधारों को आपने ताक पर रख दिया है। आप कौन से सुधार ला रहे हो? आप न वित्तीय प्रणाली में सुधार ला रहे हो, न कर प्रणाली में सुधार ला रहे हो, न उद्योग की नीति में ला रहे हो, न ही किसी अन्य क्षेत्र में ला रहे हो।

आपको मालूम है कि 90 के दशक में एक बार भारतीय उद्यमियों ने निर्णय किया था और उसके कारण उन्होंने एक चमत्कार करके दिखाया, जिसको आज तक लोग नमस्कार कर रहे हैं। भारतीय उद्यमियों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि अगर उद्योगों को आजादी दोगे तो वे क्या-क्या कर सकते हैं और उन्होंने उसे सफल बनाकर दिखाया। अब उनको आगे की आजादी चाहिए, क्योंकि उनको अभी और आगे बढ़ना है। हम अपने देश को किससे कंपेयर करेंगे? हमारे पड़ोस में चीन है, लेकिन बार-बार हम यही कहेंगे कि चीन का उदाहरण मत दो, क्योंकि वहां तानाशाही है। मंत्री महोदय, यह सही नहीं है। चीन का उदाहरण इसलिए प्रासंगिक है कि पांच साल में आप जहां 78,000 मैगावाट बिजली निर्माण का लक्ष्य रखते हो और जो आधा भी पूरा नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि या आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आपका वित्तीय संचालन ठीक नहीं है। वहीं चीन ने नये सिरे से एक लाख मैगावाट per year बिजली का निर्माण करके दिखाया है और सालों से वह करता आ रहा है। आज जहां हम 1,20,000 मैगावाट पर अटके हुए हैं, वहां वह 8 लाख मैगावाट तक पहुंच गया है। तरक्की का पैमाना यह होता है, इसको कहते हैं Fiscal Management और इसको कहते हैं वित्तीय व्यवस्थापन। इसी के सहारे आज चीन अमरीका के बेल आउट को बेल आउट कर रहा है। चीन से ही तो पैसा गया और उन्होंने अमरीका के सारे बेल आउट plants को ही परचेज़ कर लिया। उनके पास डॉलर का अपार भंडार है। हमारे पास अभी मंदी के दौर में 70-80 बिलियन डॉलर्स की कमी आई, और जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसका उपयोग करने की कितनी बार चर्चा हुई? क्या आपने उसके एक प्रतिशत पैसे का भी उपयोग किया है? आपने उसका उपयोग न इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है और न ही किसी और दूसरी चीज़ के लिए किया है। यह कोई अच्छे वित्तीय व्यवस्थापन का नमूना नहीं होता है। आपने क्या किया? आपने चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे खर्च कर दिए, जो untargeted subsidies करके बता दिए गए। आप लोग बहुत * मारते हो कि हमने किसानों के 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। वित्त मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि आज क्या स्थिति है? यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण जी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: * अच्छा शब्द नहीं है।

श्री प्रकाश जावडेकर: ठीक है, मैं * शब्द वापस ले लेता हूं।

श्री उपसभापति: * शब्द निकाल दीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकर: मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यहां पर पृथ्वीराज चव्हाण जी बैठे हुए हैं और उनको भी यह मालूम है। आज जब 16 दिसम्बर को हम यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं, विदर्भ में इस महीने आज तक की तारीख तक के 15 दिन में 22 किसानों ने आत्महत्या की है। एक साल में 926 लोगों ने आत्महत्या की है। Prime Minster Special Package लाने के बाद और आपके द्वारा कर्ज माफी के बाद हालात यह हैं। आपकी कर्ज माफी लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है। यह ठीक है कि कुछ चंद किसानों के पांच-पांच या दस-दस लाख माफ हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां पर जरूरी था, जिस विदर्भ और तेलंगाना में आत्महत्या को रोकने के लिए यह स्कीम बनाई गई थी, वहां पर आत्महत्याएं बदस्तूर जारी हैं। यह आपकी वित्तीय नीति की विफलता का एक और प्रमाण है और चुनाव फंड आपने ऐसे ही खर्च कर दिया। Populist measure लेने की आड़ में और किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए आपने जो यह सब किया है, इसकी कीमत आज देश को चुकानी पड़ रही है।

*Expunged as ordered by the Chair.

दूसरी बात, मैं यह कहता था कि प्राइम मिनिस्टर का पैकेज हो या कर्ज माफी हो, वह सही तरीके से लागू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका फायदा सबको नहीं मिला। जो जरूरतमंद किसान हैं, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। हमारी अर्थव्यवस्था में सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्ज माफ करने की क्षमता थी, लेकिन उस अवसर को आप चूक गए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है।

आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा था कि काले धन को हम 100 दिन में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन क्या हुआ?

केवल चंद पत्र आपके गए हैं। सरकार बार-बार यह कहती है कि हम स्विट्जरलैंड के साथ नेगोशिएट करेंगे। वहाँ जर्मनी देने को तैयार था, बाकी लोग भी यह जानकारी देने को तैयार थे, लेकिन आप जानकारी लेने को भी उत्सुक नहीं हैं और न ही काला धन वापस लाने को उत्सुक हैं। अपने देश में जो पैसा नए सिरे से आ सकता है और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए बिजली का निर्माण कर सकता है, सड़क का निर्माण कर सकता है तथा सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, उसको आप नहीं ला रहे हैं। यह देश के साथ बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी घोषणाएँ आपने कीं, उन पर भी क्या आपने अमल किया है? आपने अमल नहीं किया है। हर चीज में आप राज्यों को दोष देना चाहते हैं। यह कोई नीति नहीं होती है। आखिर अर्थव्यवस्था का संचालन केन्द्र की प्राथमिकता है। केन्द्र ही उसका संचालन करेगा। लेकिन, केन्द्र क्या कर रहा है, इसके केवल दो-तीन उदाहरण मैं देता हूँ। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है।

एक बात चावल एक्सपोर्ट की है। जब अपने यहाँ चावल कमी है और जब देश चावल की कमी से जूझ रहा है, तब आपके वाणिज्य मंत्रालय ने 2 लाख 25 हजार मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया। उस पर एक बार यहाँ चर्चा भी हुई। तब सरकार के द्वारा यह बताया गया कि इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, ये अफ्रीकन देश थे और 20-21 देशों को हमने मदद के रूप में humanitarian aid किया। इस पर लोगों ने पूछा कि कुछ निजी कम्पनीज़ को उसमें क्यों इनवॉल्व किया, उन्हें क्यों कंट्रैक्ट्स दिये और यह काम सरकार की एजेंसी द्वारा क्यों नहीं किया गया? तब कहा गया कि सरकारी एजेंसीज़ के द्वारा ही उनको नियुक्त किया गया है। जब पूछा गया कि उसमें टेंडर क्यों नहीं किया गया? उसका कुछ जवाब नहीं है। मैं आज केवल यह बताना चाहता हूँ कि आपके कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, आपके पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय को क्या कहा था? उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमारे यहाँ जो आज चावल के निर्यात की बात हो रही है और जो चावल भेजा जा रहा है, अपने देश में चावल की कमी है। इसलिए चिदम्बरम साहब ने कहा था कि "Rice Budget shows that we barely meet buffer norms of 52 lakh tons at 54.99 lakh tons." यह उनका अभिप्राय था। फिर कृषि मंत्री ने भी लिखा था कि "Our target was procuring 270 lakhs tones but we got only 262 lakh tones and as such Finance Minister's objections are valid." इसके बावजूद भी जब चावल का निर्यात हुआ तब उससे सरकार का घाटा हुआ और चंद कम्पनियों का फायदा हुआ, जिससे देश का सवा दो लाख मीट्रिक टन चावल बाहर गया। सब आपके नियमों और सिद्धांतों को ताक पर रख कर यह व्यवहार होता रहा। दो-दो मंत्री, जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद भी यह हुआ। आपको खुलासा करना चाहिए कि अगर इस तरह का व्यवहार होगा, तो इसे क्या वित्तीय व्यवस्थापन कहा जाएगा?

स्पेक्ट्रम का मामला तो आपके सामने है। आपको पूरक माँगें रखने की शायद जरूरत ही न पड़ती, वित्तीय घाटा भी कम होता, अगर इसमें पारदर्शिता से काम होता, क्योंकि इससे सरकार की आय बढ़ती, क्योंकि इसमें अपार सम्भावनाएँ थीं। लेकिन, 60 हजार करोड़ का * में जो लोग व्यस्त रहे और जिन्होंने

*Expunged as ordered by the Chair.

यह स्पेक्टम घोटाला किया, इसके कितने पहलू हैं। सभी पहलुओं की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं एक नया पहलू बताना चाहता हूँ। डिफेंस का जो स्पेक्ट्रम रक्षा विभाग के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, होता है झ् प्रणब दा, आप डिफेंस मिनिस्टर रहे थे-- वह एक जरूरत थी, लेकिन डिफेंस पर दबाव बना कर डिफेंस का स्पेक्ट्रम रिलीज करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को बाध्य किया गया। जब उसे बाध्य किया गया, तब जो प्रॉमिसेज़ रक्षा मंत्रालय को दिए गए थे, उसका पालन भी नहीं हुआ है। केवल होड़ है, किसी भी तरह से स्पेक्ट्रम को पाओ और स्पेक्ट्रम को बेचो, कम कीमत में बेचो और बाकी पैसा जेब में डालो। यह सारा काम चल रहा है। इसी के कारण आज स्पेक्ट्रम का घोटाला जो हुआ, उसमें 60 हजार करोड़ का * सरकार को लगा है। यह दूसरे किसी ने नहीं लगाया है, बल्कि आपके यहाँ बैठे हुए लोगों ने ही लगाया है। इसलिए जब तक यह कम नहीं होता, यह कैसा वित्तीय व्यवस्थापन है? यह देश को संचालित करने का तरीका नहीं है।

जैसे मैंने चीनी का उदाहरण दिया, वैसे और भी बहुत-सारे उदाहरण हैं। जो गेहूँ दो साल पहले आयात हुआ, उसमें से 8 लाख टन से ज्यादा आयातित गेहूँ नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वह मनुष्य के खाने के लिए ठीक नहीं था।

तो इस तरह से अगर आप एक-एक चीज़ पर काम करेंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। आखिर वित्तीय-व्यवस्थापन का क्या मापदंड होता है? अगर अच्छा वित्तीय संचालन होता है तो देश की तरक्की बहुत तरीके से होती है, Social Justice मिलता है, inclusive growth होती है, गरीब को न्याय मिलता है, महँगाई कम होती है और नये सुधारों के साथ, नयी ऊर्जा के साथ आप नये अवसरों को प्राप्त करने की होड़ में आ जाते हैं और दुनिया में हमारा सर ऊँचा होता है। वह वित्तीय-व्यवस्थापन होता है, वह तरक्की होती है और उसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है, मेरा यही कहना है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to stand here to support the Appropriation (No. 4) Bill, 2009. This Bill provides for spending of Rs. 30,942,62,00,000 for defraying expenses during 2009-10 for services of as many as 105 departments which have been mentioned in the Schedule. मुझे आश्चर्य होता है कि यह जो रकम सरकार को देश चलाने के लिए 105 डिपार्टमेंट्स को देने के लिए चाहिए, उसका बीजेपी पूरा- पूरा विरोध कर रही है! आखिर इन्हें सरकार कैसे चलाए? क्या सरकार इन्हें बंद करे? इन्हें कोई पैसा न दे? Sir, 105 departments required money and he is saying that this money should not be given! It is not good. Please keep it in mind.

Sir, we have got successful programmes like NREGA. You view it with a different eye. I would not say that you are viewing this with yellow eyes; but, you are viewing it with saffron eyes. You are opposing the entire Scheme. You have just now opposed the loan-weaver scheme. You have totally opposed this.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I only said that all farmers should be given this.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Please say it, time and again, to the people that you are opposing the loan-weaver scheme. Let the country know that you are opposing the loan-weaver scheme. Sir, we may also agree in finding fault with some system. But, you are totally opposing which is bad.

*Expunged as ordered by the Chair.

For better utilisation of money, we also have to take certain steps. We have to revisit the work culture in our departments. The attitude of 'come tomorrow', 'come next month' has to be corrected. Hon. Shri Prithviraj Chavan is sitting here. He is in-charge of the Ministry of Personnel. He can do a lot for the purpose of toning the administration. Even today, Members of Parliament take two months to get reply to a letter! It is the minimum. It, sometimes, go beyond that as well. I suggested, sometime back, for doing some experiment. Let us choose 1,000 replies received by Members of Parliament of both the Houses, give them to an independent Committee and find out that in all these 1,000 replies, which are negative in nature, the work could have been done or not. I am sure, in a minimum 50 per cent of the cases, the Committee will find that the MPs could have been obliged with a positive answer. But, it does not happen. Some experiment in this matter should be carried out.

Sir, your Appropriation Bill will be passed and nobody is going to challenge it in court. As we all know that Members of Parliament have been given some amount under the MPLADS. Unfortunately, this Scheme is in court now. The MPLADS is presently in the court as it was challenged. The arguments are held. We don't know what would be the fate of this Scheme. Therefore, you should see that such a good Scheme should not at all be challenged in any court of law and, if challenged, it should have been admitted and, after admission, it takes so much of time to pass judgment. That means the sword is hanging on our head. We do not know what is going to be the fate of this Scheme. Hence, I would urge upon the Government that in case the judgment is not favourable, we should be prepared to bring an amendment to the Constitution to safeguard our interests under the MPLADS so that people will not suffer.

I would like to say this in advance. In spite of various flaws in administration that we come across, we have got a tremendous list of achievements. I will just mention about the NREGA. The NREGA is a revolutionary scheme, appreciated world over, except some local people. The RTI Act, Sir, gives an applicant a status of an MP or an MLA, because the RTI Act says, [] An information which cannot be denied to an MP or an MLA cannot be denied to an applicant under the RTI Act.[] So, it gives the status of an MP or MLA to every applicant. This is what the UPA Government has done. We have also enacted the Forest Rights Act. Although the policy and the Act taken together is not going that fast as it should have gone, this is going to be another revolutionary legislation which the UPA Government has enacted.

Sir, the Land Acquisition (Amendment) Act which was stalled last time by our opponents should, again, be brought forward. The Land Acqusition Act contains many wonderful provisions. Today, we are acquiring land, giving compensation to those who lose the land and our job is finished. But in that Act, there is a scheme which provides that in future, before acquiring a land, a thorough assessment will be made of the impact. After the impact report

comes, only then the land will be acquired. Secondly, if a person has got a house therein, apart from giving compensation, an alternate plot will be given to that person to build a house. Jobs will be reserved for those whose land is acquired. Jobs will be given on a priority basis. These are the provisions which are contained in the Land Acquisition (Amendment) Act and the policy which was stalled by the Opposition, which we should try to have. Now, solar energy is the future energy of our country and the Government has rightly stressed on the solar energy aspect, so that we become self-sufficient, to a great extent in our energy requirements. Now, since there are various other Departments, I will be touching upon only three, four Departments where the money is going. One is the Department of Civil Aviation. In civil aviation, they have announced a number of airports which includes Mopa airport in Goa. But we say that existing Dabolim airport should be expanded and upgraded. Sir, you were the Defence Minister. You were kind enough to order Navy to give sufficient land to the civil aviation authorities but despite that, Sir, till today, Navy is creating hurdles in granting land to the civil aviation authorities; as a result of which expansion of Dabolim is not taking place and consequently, the development of Mopa airport has also been stalled. Therefore, Sir, if infrastructure has to be improved, then, these airports which have been announced by the Minister of Civil Aviation will have to develop speedily.

Another aspect I would like to mention relating to my State, Sir, is this. We require some special provisions under article 371 of the Constitution. Since Goa is a small State, we do not have land and people from other countries like Israelis, Russians and our own land sharks come with tonnes of money, buy entire villages and we do know where we stand. Therefore, I in my humble way moved a Private Member Bill , which, officially also, the Goa Government is going to place before the Government, in which we have asked for the amendment of article 371 of the Constitution to provide a provision to empower the Legislature of Goa to regulate the ownership and transfer of land in public interest, on grounds of duration of residential requirement in a State, social and economic needs of a State, environment and public interest, as may be specified by the law. Unless such a Constitutional backing is given to the State, we will not be able to enact any legislation to regulate our land. We enacted one legislation by amending the Registration Act but it was not assented to by the President of India because earlier there was some judgment of the court, and, therefore, Sir, this has been stalled. I would urge upon you, Sir, to consider this proposal.

Then, Sir, I come to giving Goa the special category status. Many States are asking for it and we are also in queue. Though the other States which are in line are not getting it, but, Sir, you know we missed two Five Year Plans. We became independent in 1961. So, Goa missed two Five Year Plans and we are the sufferers. Therefore, Sir, there is just case that small States like Goa, which was under Portuguese Rule for 450 years — Goa was under Portuguese Rule for

450 years — should be given due concession, and, for a limited number of years, we should be considered for providing 'Special Category' status apart from granting a package. We are asking for a package and we request the Central Government to kindly give it. Apart from that, we also request that the 'Special Category' status should be given to Goa.

Then, Sir, there is one more aspect. Presently, we are under AGMU cadre, the cadre of certain States and Union Territories. As a result, the officers of All India Services come to Goa. We call them 'briefcase officers' because they just come with a briefcase. They stay in Delhi. In the weekend, they come to Delhi and then go back to Goa. So, they pay no concentration as far as the welfare of Goa is concerned. They are not interested in giving any useful suggestions to local Government to improvise. They don't follow-up a project till the target is achieved. So, we don't get good services from them. Therefore, Sir, the Goa Government will be coming for asking a separate All India Services cadre for Goa. It is our constitutional right. We can't be clubbed together. We may be small. That is pending. Moreover, Sir, presently under the AGMU Cadre, what is the strength of Goa? It has only 12 officers. So, there is demand to raise it to, at least, 22 officers, apart from pending the consideration of our separate cadre. So, this should be done as early as possible. Otherwise, we will continue to suffer. Goa is having only 12 officers. I think, Sir, some other States, smaller than us, are having better strength in AGMU cadre than Goa. So, this should be considered. Prithviraj is here. I request him to take a note of this because he is the Minister who is directly concerned with that.

Then, Sir, I come to the Ministry of Information and Broadcasting. Despite the policy of the Government of India to have a full-fledged Doordarshan studio in every capital of the country, we had to struggle very, very hard for it. Though ultimately, we had a building which was recently inaugurated, yet we do not have a full-fledged studio. Forget that, Sir. Nobody would believe that we don't have a news bulletin on our Doordarshan till today, a simple news bulletin which any studio will have at any time in spite of the fact that we organize International Film Festival. The International Film Festival is organized there but the Doordarshan studio does not have a news bulletin. Sir, can anyone image that? The worst part of it, Sir, is that when the building was inaugurated by the former Minister, Shri Anand Sharmaji, he promised — he was kind enough to promise — that they will start a news bulletin soon but today I have come to know — I got a reply in the Rajya Sabha — that no proposal for starting a news bulletin is under consideration. This reply was given by Prasar Bharti. The Prasar Bharti is an independent body and the Minister only replies. Sir, Prasar Bharti has gone to that extent that it does not listen to anybody. They don't bother about the Minister or the Ministry, and, Sir, I think, it is time the Prasar Bharti is wound up if they don't respond to the public aspirations.

Then, Sir, there is one other thing as far as my State is concerned. I request that an appellate tribunal under Customs Act be established in Goa which should cover Belgaum, Sindhudurg, Karwar, Dharbar, Hubli and Goa. Around 4000 cases are pending in this region. At present, we have got five Benches in Mumbai, Chennai, Delhi, Bangalore and Kolkata. So you can have an appellate tribunal Bench in Goa which can cover all these areas and can be beneficial to all of us.

Then, Sir, this attitude of merging an independent State into another State should be discouraged. Now, I will give an example. The Post and Telegraph Department does not recognise Goa as an independent State under the Constitution of India. They say it is a district. How can a Department of the Government of India treat a fullfledged State as a district? We are treated as a district. Our demand is that Goa should be treated as a State and we should have a full-fledged Circle for the Postal Department as also for the Telephone Department.

Then, Sir, if administration is to be taken to the doorsteps of the Government, e-governance is the only alternative. We are talking of egovernance. We have taken a lot of steps; there is no doubt about it. But till today, effective e-governance is not there. Why cannot officers or the Ministers reply to us through e-mail? Why should a reply come only in two months? Let us say, I send an e-mail in seven or eight days' time — it is not easy, Sir; it is very difficult; and the information is available only on the website; they give information after information — they can reply to us within eight days instead of two months. Let them deal with the State Governments through e-mail. Today, they take one month to write a letter, one month to post the letter, and you know what happens thereafter. So, communication with the State Governments should be carried out through e-mail, if administration has to be made effective.

Lastly, Sir, our powers must be restored. We are saying that we are helping others, but our powers have been taken away. Restore our own powers. The other day, the Law Minister had made a statement on the appointment of Judges — appointments of Judges are made as per decision 'so and so' and read with the advisory opinion of the Judges. So, we do not have any powers to enact legislations for appointment of Judges! Is this law to be continued on some judgement and some advisory opinion? Every action of ours, every legislation, everything, including schemes under MPLAD, is being challenged in the Supreme Court of India. Where do we have the powers? Therefore, Sir, let us have a special Session in order to restore our powers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mohammed Amin; you have ten minutes.

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं दस मिनट के अंदर ही समाप्त कर दूंगा। आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

"बयां की सादगी दिल पर असर अंदाज होती है,
मुफ़स्सिर की सदा में वक्त की आवाज होती है।"

इन्होंने एप्रोप्रिएशन बिल के तहत 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमाण्ड की है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है और यह समझने की जरूरत है कि इस हुकूमत की financial policy क्या है, Taxation की policy क्या है? इस सिलसिले में मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। पिछले साल बजट स्पीच में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि 4.8 लाख करोड़ रुपए का बिग हाउस और कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में concession दिया गया है। यह concession क्यों दिया गया है? यह concession incentive देने के लिए दिया गया है। इसका हिसाब ऐसा बनता है कि 3.23 परसेंट concession बिग हाउस को दिया गया और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसमें एलपीजी गैस, केरोसिन तेल, आदि चीजें आती हैं, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया, वह इससे तीन गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब के मुंह से निवाला छीन कर बड़े लोगों के पेट में घुसा देना। फिर आम आदमी की बात तो बेकार बात हुई न। अगर आम आदमी की बात करके पूंजीपतियों की सेवा करने की नीति अपनाई जाए, तो यह कभी भी सेहतमंद नीति नहीं हो सकती है और इससे देश का कल्याण नहीं होगा। लैण्ड रिफॉर्म की बात भी कहीं नहीं सुनी जाती है। एक जमाना था, जब कि कांग्रेस के बड़े नेता बड़े जोरों से प्रचार करते थे कि जब हम लोगों के हाथ में इक्तिदार आएगा, तो तमाम जमीन किसानों में बांट देंगे। अगर इस काम को अंजाम दिया गया होता, तो हिन्दुस्तान में और किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। मजे से राज चलता और कांग्रेस को लोग दोनों हाथों से समर्थन करते, लेकिन वह सिर्फ कागज पर ही लिखा रह गया। अभी हम लोग पूरे हिन्दुस्तान में देखते हैं, तो आज भी अगर कहीं लैण्ड रिफॉर्म का काम जारी है, तो वह पश्चिमी बंगाल में है। वहां 40 लाख एकड़ ज़मीन तो बांटी जा चुकी है और जो मुकदमों में ज़मीन फंसी हुई है, वह जब मुकदमों से छूटती है, तो वह भी बांट दी जाती है और यह काम आगे बढ़ रहा है। बाकी किसी जगह लैंड रिफॉर्म की कोई बात सुनी नहीं जाती है।

सर, यह बात आज भी सच है कि अगर गरीबों को राहत पहुंचानी है, अगर उनके हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो उनको ज़मीन देनी होगी, ज़मीन का मालिक बनाना होगा, ताकि वे फसल के मालिक बनें। जब उनके हाथ में पैसा जाएगा, तो उनकी कुव्वते-खरीद बढ़ेगी और जब उनकी कुव्वते-खरीद बढ़ेगी, तो कल-कारखाने बनेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पूरा देश तरक्की करेगा। जब यह नहीं हो रहा है, तो नतीजा क्या हुआ कि जो कलका रखाने बने हुए हैं, वे भी बंद होते जा रहे हैं और सरकार के हाथ में जो कारखाने हैं, जो मुनाफे पर चल रहे हैं, उनके बारे में इस साल ऐलान ही कर दिया है कि उसका दस परसेंट disinvestment किया जाएगा। यह तो किसी की समझ में नहीं आता कि यह क्या बात हुई और इससे देश किस तरफ जाएगा?

सर, इसके अलावा मैं समझता हूं कि इस साल तो महंगाई की मार से लोगों की सांस उखड़ गई है। देश की आज़ादी के बाद इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई जब आलू 30 रुपए किलो, प्याज़ 35 रुपए किलो, अरहर की दाल 95 रुपए किलो, इस भाव पर पहुंच गई है। लोग कहते हैं कि दाल-रोटी से गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन जब दाल भी महंगी होगी, रोटी भी महंगी होगी तो किस चीज़ पर गुज़ारा होगा? अब सिर्फ पानी पियो और हवा खाओ, इसके अलावा तो और कुछ रह नहीं गया है। इसलिए अगर सरकार समझती है कि हमको राजगद्दी पर बैठा दिया गया है, अब हम जैसे भी चाहें, चलाएं तो यह बात समझनी चाहिए कि पांच साल तक तो यह चल सकता है, उसके बाद नहीं चलेगा। लोग जब नाराज़ हो जाएंगे, तो वे फिर इनको उधर से उठाकर इधर बैठा देंगे और जिस नीति को, जिस पॉलिसी को वे ठीक समझेंगे, करेंगे।

सर, महंगाई के बारे में जब सरकार यह क्लेम करती है कि everything is well under control, prices are under control, तो इस पर हंसी आती है। इसलिए कि सरकार में जो मंत्री हैं, पता नहीं वे खुद बाज़ार जाते हैं या नहीं जाते हैं, इनको मालूम भी है या नहीं कि दाम कितने बढ़े हैं। अगर इन्हें यह बात मालूम होती, तो कम से कम यह दावा तो नहीं करते कि कीमतें कंट्रोल में हैं। कीमतें एक साल के अंदर दोगुनी हो गई हैं और लोगों की जो आमदनी है, वह भी बढ़ी नहीं है, घट रही है, job loss हो रहा है, रोज़गार छीने जा रहे हैं,

disinvestment हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिर कैसे माना जाए कि आम आदमी के बारे में कोई बात ये लोग कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं?

सर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यह हालत है, तो सरकार बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी इज़राइल से कर रही है। आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अखबारों के ज़रिए यही मालूम होता है कि इज़राइल से हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान से पैसा लेकर इज़राइल फिलीस्तीनियों के ऊपर ज़ुल्म कर रहा है। फिलीस्तीनियों को गाज़ा पट्टी में धकेल कर उसको एक बहुत बड़े कैदखाने में तब्दील कर दिया है और इतनी मुसीबत भरी उनकी ज़िंदगी बन गई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जब दुनिया को यह मालूम होता है कि उसी इज़राइल से हिंदुस्तान हथियारों की खरीदारी कर रहा है, तो इससे हिंदुस्तान की बड़ी बदनामी होती है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, तो बहुत अच्छा होगा।

सर, प्रकाश जी Spectrum की बात कह ही चुके हैं। अभी WTO की मीटिंग हुई, तो WTO की जो agricultural policy है, उससे हिंदुस्तान के किसान तबाह हो रहे हैं। हर साल लाखों लोग गले में रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जान दे देते हैं, मगर सरकार का उधर ध्यान ही नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में इतने लोग आत्महत्या करके नहीं मरते। इसकी वजह क्या है कि किसानों की फसल जब तैयार होती है, तो सरकार भी नहीं खरीदती और कोई खरीदार नहीं मिलता है। फसल का दाम जब गिर जाता है, तो फसल बिकती है। उसके बाद खरीद के जो बिचौलिए हैं, वे मालदार बन जाते हैं। किसान को जब उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती और महाजन का तकाज़ा शुरू हो जाता है, जब इज्ज़त-आबरू नीलाम होने लगती है, तो गले में रस्सी का फंदा डालकर अपनी जान देने के सिवाय उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहता है।

यह आम आदमी की बात हुई। किसानों को बचाने के साथ-साथ बाजार की महंगाई का सवाल भी जुड़ा हुआ है। एक मंत्री महोदय ने बयान दिया था कि हम लोगों के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बाजार की महंगाई को कम कर दें। आपके पास जादू की छड़ी है, लेकिन आप उस रास्ते पर कदम नहीं रखते हैं। जादू की छड़ी यही है कि जब फसल तैयार हो तो गांव के लोगों की जरूरतों को छोड़कर के किसानों को मुनासिब दाम देकर सरकार उनकी फसल जैसे- चावल, दाल, तेल, गेहूं, शक्कर तमाम चीजों को खरीद ले और पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के जरिए से पूरे देश के लोगों को कंट्रोल रेट पर सप्लाई करे, बाजार की महंगाई उतर जाएगी। चीन ने इसी रास्ते पर चलकर महंगाई को कंट्रोल किया है। यही इसकी गारंटी है कि चीन में महंगाई नहीं बढ़ती है, लोगों की तनख्वाह बढ़ती है। चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आप उनसे यह सीखें कि उन्होंने यह कैसे किया है। अगर पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन को मजबूत किया जाए, तो करोड़ों की तादाद में दुकानें खुलेंगी और बहुत लोगों को रोजी-रोटी मिलेगी, किसानों को बचाया जा सकेगा तथा बाजार की महंगाई भी कम हो जाएगी। मगर इसमें एक बात है। ये क्यों नहीं, उस रास्ते पर जा रहे हैं, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और यही वे लोग हैं जो चुनाव के मौके पर मोटी-मोटी रकमें चुनाव के फंड में देते हैं जिससे चुनाव जीतकर ये लोग राज-गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं। बस यही रुकावट है, वरना बाजार की महंगाई कम करने का रास्ता खुला हुआ है। अगर इस रास्ते पर आप चलें, तो देश का भला हो सकता है। सर, मैं दस मिनट से पहले ही खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं एक शेर आपको सुनना चाहता हूं:-

"वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाता है,
बदले दुश्मन तो निशाना भी बदल जाता है,
जिंदगी अपने तजुर्बे से यही समझाती है,
सांस बदले तो तराना भी बदल जाता है।"

جناب محمد امین (مغربی بنگال): مہودے، میں دس منٹ کے اندر ہی سماپت کر دونگا۔ آپ کو گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

بیاں کی سادگی دل پر اثر انداز ہوتی ہے
مفسر کی صدا میں وقت کی آواز ہوتی ہے

انہوں نے اپروپرنیشن بل کے تحت جو 30 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حکومت کی فائنینشنل پالیسی کیا ہے، ٹیکسیشن کی پالیسی کیا ہے؟ اس سلسلے میں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ پچھلے سال بجٹ اسپیچ میں مائنے منتری جی نے یہ کہا تھا کہ 4-8 لاکھہ کروڑ روپے کا بگ ہاؤس اور کارپوریٹ سیکٹر کو ٹیکس میں کنسیشن دیا گیا ہے۔ یہ کنسیشن کیوں دیا گیا ہے؟ یہ کنسیشن انسینٹو دینے کے لئے دیا گیا ہے۔ اس کا حساب ایسا بنتا ہے کہ 3-23 فیصد کنسیشن بگ ہاؤس کو دیا گیا اور جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہوتا ہے، جس میں ایل‌پی‌جی۔ گیس، کیروسن تیل وغیرہ چیزیں آتی ہیں، جس کا استعمال زیادہ تر غریب لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا، وہ اس سے تین گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب کے منھہ سے نوالہ چھین کر بڑے لوگوں کے پیٹ میں گھسا دینا۔ پھر عام آدمی کی بات تو بیکار بات ہوئی نا۔ اگر عام آدمی کی بات کرکے پونجی‌پتیوں کی سیوا کرنے کی نیتی اپنائی جائے، تو یہ کبھی بھی صحت مند نیتی نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے دیش کا کلیان نہیں ہوگا۔ لینڈ ریفارم کی بات بھی کہیں نہیں سنی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، جب کہ کانگریس کے بڑے نیتا بڑے زوروں سے پرچار کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں کے ہاتھہ میں اقتدار آئے گا، تو تمام زمین کسانوں میں بانٹ دیں گے۔ اگر اس کام کو انجام دیا گیا ہوتا، تو ہندوستان میں اور کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزے سے راج چلتا اور کانگریس کو لوگ دونوں ہاتھوں سے سمرتھن کرتے، لیکن وہ صرف کاغذ پر ہی لکھا رہ گیا۔ ابھی ہم لوگ پورے ہندوستان میں دیکھتے ہیں، تو آج بھی اگر کہیں لینڈ ریفارم کا کام جاری ہے، تو وہ پشچھمی بنگال میں ہے۔ وہاں 40 لاکھہ ایکڑ زمین توبانٹی جا چکی ہے اور جو مقدموں میں زمین پھنسی ہوئی ہے، وہ جب مقدموں سے

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

چھوٹتی ہے، تو وہ بھی بانٹ دی جاتی ہے اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی کسی جگہ لینڈ ریفارم کی کوئی بات سنی نہیں جاتی ہے۔

سر، یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر غریبوں کو راحت پہنچانی ہے، اگر ان کے ہاتھ میں پیسہ پہنچانا ہے، تو ان کو زمین دینی ہوگی، زمین کا مالک بنانا ہوگا، تاکہ وہ فصل کے مالک بنیں۔ جب ان کے ہاتھ میں پیسہ جائے گا، تو ان کی قوت خرید بڑھے گی اور جب ان کی قوت خرید بڑھے گی، تو کل کارخانے بنیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، پورا دیش ترقی کرے گا۔ جب یہ نہیں ہو رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ جوکل-کارخانے بنے ہونے ہیں، وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں اور سرکار کے ہاتھ میں جو کارخانے ہیں، جو منافع پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اس سال اعلان ہی کر دیا ہے کہ اس کا دس فیصد disinvestment کیا جائے گا۔ یہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہوئی اور اس سے دیش کس طرف جائے گا؟

سر، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال تو مہنگائی کی مار سے لوگوں کی سانس اکھڑ گئی ہے۔ دیش کی آزادی کے بعد اتنی مہنگائی آج تک کبھی نہیں ہوئی جب آلو 30 روپے کلو، پیاز 35 روپے کلو، ارہر کی دال 95 روپے کلو، اس بھاؤ پر پہنچ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دال-روٹی سے گزارہ ہو جائے گا، لیکن جب دال بھی مہنگی ہوگی، روٹی بھی مہنگی ہوگی تو کس چیز پر گزارہ ہوگا؟ اب پانی پیو اور ہوا کھاؤ، اس کے علاوہ تو اور کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ اس لئے اگر سرکار سمجھتی ہے کہ ہم کوراج گدی پر بیٹھا دیا گیا ہے، اب ہم جیسے بھی چاہیں، چلائیں تو یہ بات سمجھنی چاہئے کہ پانچ سال تک تو یہ چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چلے گا۔ لوگ جب ناراض ہو جائیں گے، تو وہ پھر ان کو ادھر سے اٹھاکر ادھر بیٹھا دیں گے اور جس نیتی کو، جس پالیسی کو وہ ٹھیک سمجھیں گے، کریں گے۔

سر مہنگائی کے بارے میں جب سرکار یہ claim کرتی ہے کہ everything is well under control, prices are under control, تو اس پر ہنسی آتی ہے۔ اس لئے کہ سرکار میں جو منتری ہیں، پتہ نہیں وہ خود بازار جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے یا نہیں کہ دام کتنے بڑھے ہیں۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی، تو کم سے کو یہ دعوی تو

نہیں کرتے کہ قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ قیمتیں ایک سال کے اندر دوگنی ہو گئی ہیں اور لوگوں کی جو آمدنی ہے، وہ بھی بڑھی نہیں ہے، گھٹ رہی ہے، job loss ہو رہا ہے، روزگار چھینے جا رہے ہیں، disinvestment ہو رہا ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو پھر کیسے مانا جائے کہ عام آدمی کے بارے میں کوئی بات یہ لوگ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟

سر، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حالت ہے، تو سرکار بہت بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری اسرائیل سے کر رہی ہے۔ آنکڑے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اخباروں کے ذریعے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل سے ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہندوستان ہے اور ہندوستان سے پیسہ لے کر اسرائیل، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں دھکیل کر اس کو ایک بہت بڑے قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے اور اتنی مصیبت بھری ان کی زندگی بن گئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ اسی اسرائیل سے ہندوستان ہتھیاروں کی خریداری کر رہا ہے، تو اس سے ہندوستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر سرکار اس پر دھیان دے، تو بہت اچھا ہوگا۔

سر، پرکاش جی spectrum کی بات کہہ ہی چکے ہیں۔ ابھی ڈبلیو۔ٹی۔او۔ کی میٹنگ ہوئی، تو ڈبلیو۔ٹی۔او۔ کی جو ایگریکلچر پالیسی ہے، اس سے ہندوستان کے کسان تباہ ہو رہے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ گلے میں رسّی کا پھندا لگا کر اپنی جان دے دیتے ہیں، مگر سرکار کا ادھر دھیان ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنے لوگ آتماہتیہ کرکے نہیں مرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسانوں کی فصل جب تیار ہوتی ہے، تو سرکار بھی نہیں خریدتی اور کوئی خریدار نہیں ملتا ہے۔ فصل کا دام جب گر جاتا ہے، تو فصل بکتی ہے۔ اس کے بعد خرید کے جو بچولیے ہیں، وہ مالدار بن جاتے ہیں۔ کسان کو جب اس کی فصل کی قیمت نہیں ملتی اور مہاجن کا تقاضہ شروع ہو جاتا ہے، جب عزت و آبرو نیلام ہونے لگتی ہے، تو گلے میں رسّی کا پھندا ڈال کر اپنی جان دینے کے سوائے اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ یہ عام آدمی کی بات ہوئی۔ کسانوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ بازار کی مہنگائی کا سوال بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک منتری مہودے نے بیان دیا تھا کہ ہم لوگوں

کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بازار کی مہنگائی کو کم کر دیں۔ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، لیکن آپ اس راستے پر قدم نہیں رکھتے ہیں۔ جادو کی چھڑی یہی ہے کہ جب فصل تیار ہو تو گاؤں کے لوگوں کی ضرورتوں کو چھوڑ کر کے کسانوں کو مناسب دام دے کر سرکار ان کی فصل جیسے چاول، دال، تیل، گیہوں، شکر تمام چیزوں کو خرید لے اور پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم کے ذریعے سے پورے دیش کے لوگوں کو کنٹرول ریٹ پر سپلائی کرے، بازار کی مہنگائی اتر جائے گی۔ چین نے اسی راستے پر چل کر مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے۔ یہی اس کی گارنٹی ہے کہ چین میں مہنگائی نہیں بڑھتی ہے، لوگوں کی تنخواہ بڑھتی ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ ان سے یہ سیکھیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا ہے۔ اگر پبلک ڈسٹری بیوشن کو مضبوط کیا جائے، تو کروڑوں کی تعداد میں دکانیں کھلیں گی اور بہت لوگوں کو روزی روٹی ملے گی، کسانوں کو بچایا جا سکے گا اور بازار کی مہنگائی بھی کم ہو جائے گی۔ مگر اس میں ایک بات ہے۔ یہ کیوں نہیں، اس راستے پر جا رہے ہیں، جو کروڑپتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا اور یہی وہ لوگ ہیں جو چناؤ کے موقع پر موٹی موٹی رقمیں چناؤ کے فنڈ میں دیتے ہیں جس سے چناؤ جیت کر یہ لوگ راج گدی پر آکر بیٹھ جاتے ہیں، بس یہی رکاوٹ ہے، ورنہ بازار کی مہنگائی کم کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس راستے پر آپ چلیں، تو دیش کا بھلا ہو سکتا ہے، سر، میں دس منٹ سے پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، لیکن میں ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں:

وقت کے ساتھ زمانہ بھی بدل جاتا ہے
بدلے دشمن تو نشانہ بھی بدل جاتا ہے
زندگی اپنے تجربے سے یہی سمجھاتی ہے
سانس بدلے تو ترانہ بھی بدل جاتا ہے

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. Mr. Amar Singh, you have ten minutes.

SHRI AMAR SINGH (Uttar Pradesh): I may take one or half a minute more, Sir. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरे लिए बड़े असमंजस की स्थिति है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी सदन में बैठे हैं, यह हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं और मैं इनका हृदय से आदर करता रहा हूं। इनकी गिनती देश के गिने-चुने राजनेताओं में है, जिन्होंने भारतीय राजनीति के सभी रंग देखे हैं। एक वीरभूमि के मध्यवर्गीय परिवार से आकर अगर इन्होंने गरीब किसान के हल की आहट का अहसास किया है, तो कालांतर में कम्प्युटर की key Board की खन-खनाहट को भी वह बखूबी पहचानते हैं। अगर उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में न्युक्लियर डील का समझौता कराकर के कांग्रेस की डूबती नैया को पार कराया है, तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एक ऐसा नेता, जो नेता अच्छा हो, जिसकी नीति अच्छी हो और जिसकी नीयत भी अच्छी हो, नेता, नीति, नीयत तीनों अच्छी हो। फिर भी, इन्फ्लेशन जारी है, फिर भी, महंगाई हो रही है, फिर भी आम आदमी कराह रहा है, फिर भी, न तेल मिल रहा है, न दाल मिल रही है, फिर भी, धान की कीमतें सरकार हजार रुपया तय करती है और किसान आठ सौ रुपये में निजी आढ़तियों को धान बेचता है। जो शराब का धंधा करते थे, बड़े-बड़े होटल चलाते थे, वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, चाहे वह आईटीसी हो, कारगिल हो, अदानी हो, अम्बानी हो, अब वे किसानों का पेट काटने में भी जुट गए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने "नरेगा" की योजना बनाई, जिन जॉन रेज़ ने माननीय सोनिया गांधी जी के साथ बैठकर इस योजना को बनाया, उन जॉन रेज़ का कहना है कि "नरेगा" सफल नहीं हुई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं "नरेगा" के मंत्री विज्ञान भवन में, एक बड़े युवा नेता जिनको सभी प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं, आप सब भी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनकी उपस्थिति में मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि "नरेगा" में गड़बड़ियां हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं, अपने इधर बैठे साथियों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत आसान है इल्जाम लगा देना, लगभग 14 साल मुझे इस सदन में हो गए हैं, लेकिन मैंने यहां पर भाषण की रौ को बदलते नहीं देखा है। जब ये उधर बैठते हैं तो उधर जाकर वही कहते हैं, भाषण वही रहता है, भाषण पर कोई राशन नहीं है, लेकिन राशन पर बहुत भाषण हैं।

वही गरीबी की बात, वही गुरबत की बात, वही भ्रष्टाचार की बात। मुझे याद है, यहां हमारे दोस्त अरुण शौरी जी नहीं बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त प्रमोद महाजन जी अब नहीं रहे, बहुत प्यारे दोस्त थे, हम उनकी कमी महसूस करते हैं, भले ही वे हमारे विरोधी रहे हैं, जब वे DISINVESTMENT MINISTRY से हटाए गए और जब टाटा और बी.एस.एन.एल. का विनिवेश हुआ तो उसमें बी.एस.एन.एल.में ज्यादा पैसा था और उससे कम दाम में बी.एस.एन.एल का विनिवेश हो गया। जब मैंने सवाल उठाया तो और कोई नहीं टाटा ने मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया, मैं बड़ी मुश्किल से मुकदमा लड़कर टाटा से जीता। मैं कहना चाहता हूं - हम यह तो नहीं कह सकते कि टाटा भ्रष्टाचारी हैं, वे देश के बहुत बड़े कार्पोरेट उद्योग के जनक हैं, हम यह नहीं कह सकते कि अरुण शौरी जी ने कोई गड़बड़ी की होगी, भले ही हम उधर बैठते हों, लेकिन अरुण शौरी जी के बारे में कोई कुछ कहे, उनकी ईमानदारी के बारे में कुछ कहे, यह सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन निर्णय तो गलत हो गया। डॉ. मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, उनके वित्तमंत्रित्व काल में सबसे बड़ा घोटाला हर्षद मेहता का हुआ, लेकिन किसी ने उन पर इल्जाम नहीं लगाया कि इस घोटाले के पीछे वे हैं। मैंने देखा है कि विरोध करने का एक सामान्य तरीका हो गया है कि विरोध करना है। विरोध सामूहिक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और व्यावहारिक होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे आडवाणी जी याद आ रहे हैं, मुझे हमारे स्वर्गीय बहुत प्यारे दोस्त माधव राव सिंधिया जी याद आ रहे हैं, जिनके साथ

हमने रात-दिन काम किया। डायरी के पन्नों में उनका नाम पकड़ा गया। जस्टिस वर्मा का हथौड़ा बजा। धवन जी, इसी सदन में, नरसिम्हाराव जी के मंत्रालय से तमाम लोगों को इसी समय त्याग-पत्र देना होगा, की बात हुई। यह हो गया कि पूरी राजनीतिक जमात भ्रष्टाचार में आकंठित डूबी हुई है। मैं किसी कोड़ा की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। आज मैंने प्रश्न काल में पूछा, सौभाग्य से प्रणब दा थे, कोड़ा अपराधियों को जरूर पकड़िए, लेकिन मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यूनियन बैंक ने, जिसके लिए बड़ा कोलाहल मच रहा है, इस पूरे अकाउंट को सही नहीं ठहराया है? मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अखबार की सुर्खियों से निर्धारित होगा या जज के हथौड़े से निर्धारित होगा? यहां पर कुछ लोग Accountability of Judiciary की बात कह रहे थे। लिब्रहान रिपोर्ट अयोध्या के लिए होती है, लेकिन उस पर टिप्पणी राजनेताओं के लिए आती है। जस्टिस वर्मा राजनेताओं के बारे में टिप्पणी कर देते हैं। यह एक फैशन चल गया है। हम सब, चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, बीच में बैठने वाले लोग हों, चाहे आप लोग हों, कम से कम आप यह देखिए की भ्रष्ट से भ्रष्ट राजनेता अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ न कुछ काम करता है। अगर वह भ्रष्ट है तो उसकी Accountability है। उसकी Accountability इतनी है कि उसको पांच साल में जनता निकालकर बाहर कर देती है, लेकिन अपनी राजनीति के लिए आप जो उसकी Reputation को चोट पहुंचाते हैं, उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। किसी महिला के चरित्र के बारे में और किसी पुरुष के भ्रष्टाचार के बारे में यह टिप्पणी कर देना बहुत आसान है, लेकिन इस पद्धति में हम देश का, समाज का और व्यक्तित्व का कितना नुकसान करते हैं, यह देखने की बात है। अभी Infrastructure की बात हुई। उसमें कहा गया कि हमारा 78,000 मेगावाट का लक्ष्य है और चीन से तुलना की गई। हमारे एक साथी ने कहा कि चीन से हमारे अच्छे संबंध हैं। अक्साई चीन भारत का अंग नहीं है, अरुणाचल भारत का अंग नहीं है, कश्मीर में पाकिस्तान हस्तक्षेप कर सकता है, भाई साहब, अगर चीन से अच्छे संबंधों में यह हाल है, यदि बुरे होते तो अल्लाह जाने क्या होता। आप चीन के विकास की बात करते हैं, तो चीन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि चीन में कोई PIL नहीं हो सकती है। चीन में एक circular होता है कि प्रणब मुखर्जी साहब को यह सत्ता दे दीजिए, लेकिन कोई मेधा पाटेकर नहीं आएगी, कोई PIL नहीं होगा। खुले आम गांव के गांव खाली हो जाएंगे तो 78,000 नहीं, बल्कि 150,000 मेगावाट की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार में सब अच्छा ही हो रहा है। WTO के बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं प्रणब दा से कहना चाहता हूं कि WTO की Green Box Subsidy बड़ी खतरनाक है। जिस तरह की सब्सिडी पश्चिमी देश अपने किसानों को देते हैं, उस तरह की सब्सिडी वित्त मंत्री की हैसियत से आप नहीं दे सकते हैं। वे सब्सिडी आप नहीं दे सकते तो अगर अमरीका के दबाव में विश्व स्तर पर बाजार खोल दिया जाएगा तो भारत का किसान मर जाएगा। आप WTO की बात जाने दीजिए, आपने ASIAN COUNTRIES के साथ जो करार किया है, सिंगापुर और छोटे-छोटे देश जो भारत के नजदीक हैं, ASIAN COUNTRIES के करार के कारण ये इतने समुन्त हैं - यहां हमारे रवि साहब और तमाम केरल के सांसद बैठे हैं, इनसे पूछिए कि केरल के कॉफी और रबड़ के किसानों का क्या हाल है। उन लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। क्योंकि वे आपके दल के माननीय सदस्य हैं, वे आवाज उठा सकते हैं, लेकिन एक स्तर के बाद वे चुप हो जाएंगे।

मैं आज यह जानना चाहता हूँ कि Global Hunger Index में भारत का स्थान क्या है? यह जो sensex है, यह sensex देश के समुन्नत विकास का मानक नहीं है, यह देश के 15-20 लोगों के विकास का मानक है। देश के विकास का मानक है नरेगा की योजना। यह योजना बिचौलियों की जेब में नहीं जानी चाहिए, आपने बुंदेलखण्ड के लिए योजना बनाई, पूर्वांचल के लिए योजना बनाई, लेकिन अगर आप इसकी monitoring नहीं करेंगे, तो इस योजना का सारा धन, मैं राजीव जी को उद्धृत कर रहा हूँ, उन्होंने मुम्बई के अधिवेशन में कहा था कि सारा का सारा धन, 90 प्रतिशत धन सिस्टम में प्रत्येक लोग खा जाएंगे, जो नीचे से ऊपर तक हैं।

यहाँ पर defence के बारे में भी लोगों ने चर्चा की। Defence की preparedness कैसे होगी? अभी defence के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि लोग राजनीतिक फैसले लेने से डरते हैं। कल अगर मैं रक्षा मंत्री, मैं नहीं कहता कि मैं बनूँगा, अगर मुझे अवसर मिलेगा, तो मैं हाथ जोड़ूँगा, क्योंकि यह निश्चित है कि हमारे मंत्रित्व काल के बाद हमारे ऊपर सीबीआई की जाँच बैठेगी। जो विरोधी दल आएगा, वह बिठाएगा। अगर आप defence preparedness के लिए कुछ भी करिएगा, अगर आप कोई सौदा करिएगा, तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा। अगर आपका मंत्री होगा, तो ये लगा देंगे और आपका मंत्री होगा, तो ये लगा देंगे। हम बीच वाले भारत की जनता की तरह पिसते रहेंगे।

मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रस्तावित 30,942 करोड़ के अतिरिक्त खर्च में cash outgo 25,725 करोड़ का है, जो 2009-10 के estimated budget से ज्यादा अलग नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि इससे आपकी नियोजन की क्षमता का एहसास होता है। दूसरी बात, इस प्रस्ताव में 3,458 करोड़ की food subsidy और 3,000 करोड़ की fertilizer subsidy है। यह अतिरिक्त खर्च सीधा आम आदमी और किसान के हित में है। इसके लिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कालाबाजार में चार-पाँच गुना दाम पर खाद बेची जा रही है, यह किसानों को नहीं मिल रही है, fertilizer subsidy का पूरा का पूरा लाभ कालाबाजारियों और बिचौलियों की जेब में चला गया है। प्रणब दा, खाद्य पदार्थ के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अच्छे नेता, अच्छी नीति, अच्छी नीयत होने के बावजूद इसका लाभ नीचे तक percolate क्यों नहीं हो रहा है? अगर food subsidy का फायदा आम जनता को नहीं मिलता है, तो इसका लाभ मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।

Defence pension और छठे वेतन आयोग के बजट पर बढ़े बोझ से हमारे दल को कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। सरकार की विनिवेश नीति पर मुझे सबसे बड़ी परेशानी इस बात पर थी कि विनिवेश से प्राप्त धन National Investment Fund में जाएगा या नहीं, लेकिन National Investment Fund में 3,139 करोड़ के भुगतान से मुझे काफी खुशी है, पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि National Investment Fund में 3,139 करोड़ की यह राशि जो आपने रखी है, इसका इस्तेमाल वादे के मुताबिक सामाजिक विकास के कामों में, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हो, उनमें करिए। वित्त मंत्री जी, मैं स्वास्थ्य सम्बन्धी संसदीय स्थाई समिति का अध्यक्ष हूँ और इस रूप में मैंने देखा है कि कई बार जो सचिव आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, वे कहते हैं कि आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। हमारे संविधान में यह लिखा है कि यह welfare State है। जिस तरह से right to freedom of speech है, उसी तरह right to education है, जिसके लिए कपिल सिब्बल जी बिल ला रहे थे। उसी तरह right to get free health facility भी हमारा एक अंग है। अगर इस राशि का उपयोग हेल्थ में भी थोड़ा बजट बढ़ाने में करेंगे, तो अच्छा होगा।

हमारे दोस्त प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ बैठे हुए हैं। वे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। राजनीति में मेरे कम दोस्त हैं, उनमें से एक ये हैं। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, वे इसे व्यक्तिगत नहीं लेंगे। इनसे मैं पहले अग्रिम क्षमा याचना करते हुए कहना चाहता हूँ कि एयर इंडिया को 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं जब भी न्यूयार्क जाता हूँ, आपने न्यूयार्क के लिए बहुत अच्छी एयरलाइन लगाई है, लेकिन अभी किसी ने कहा कि 7 हजार करोड़ का घाटा है, किसी ने कहा कि 5 हजार करोड़ का घाटा है, किसी ने बता दिया कि 15 हजार करोड़ का घाटा है। आपका सौभाग्य है कि आप मंत्री हैं। मैं तो हरदम सड़क पर था, सड़क पर हूँ और सड़क पर रहूँगा। इसलिए सुनी-सुनाई बातें करता हूँ। आँकड़े गलत हों, तो मुझे माफ करिएगा। घाटा 5 हजार करोड़ का हो, 7 हजार करोड़ का हो या 15 हजार करोड़ का हो, लेकिन करोड़ों का घाटा है। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि एयर इंडिया को यह 800 करोड़ की दी हुई सहायता, यह अन्तिम है या दी हुई सहायता का आगाज है, अंजाम अभी और है कि

देते रहेंगे, देते रहेंगे, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि चिन्ता यह है कि Emirates हमारे भारत सरकार की aviation policy की वजह से अमीर एयरलाइन हो गई।

जो हमारे पॉपुलर रूट्स थे और जिन पॉपुलर रूट्स पर हमको बिज़नेस मिलता था, वहां आज Emirates Airlines के कई जहाज चल रहे हैं। हमारे स्वदेश का जो धंधा है, वह Emirates के अमीरों को इतना मिल गया है कि अब दुबई के क्राइसिज़ के सॉल्यूशन के लिए अबु धाबी के शेख यह कह रहे हैं कि यह Emirates को दे दो और फिर से अमीर हो जाओ। इस तरह आपने Emirates को अमीर बनाया। आप जैट एयरवेज़ के नरेश गोयल या विजय मालया को अमीर बना देते, क्योंकि इनकी गुरबत तो अभी तक कायम है। अगर ऐसा होता, तब भी हमें एक संतोष रहता कि हमारे स्वदेशी तो बने हैं।

मैं कहूंगा कि आप इन मुद्दों पर अपना पूरा ध्यान दें। मैं अपने इधर के सभी साथियों और उधर के सभी साथियों को हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता में आएं तो देश की चिंता करें, भ्रष्टाचार हटाने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता न ढूंढ़ें और भाषण देने के लिए गरीबों की बात न करें। मुझे शैलेन्द्र का एक गीत याद आता है, जो हम सबके लिए बड़ा सामयिक है, जिसमें मैं भी शामिल हूं -

लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया।
बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है।।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Malaisamy. You have five minutes. ...*(Interruptions)*... Only five minutes. I will take the help of bell to remind you after four minutes!

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for allowing me to speak on the Appropriation Bill seeking the approval of Supplementary Expenditure of Rs.33,942.62 crores.

We are familiar with this periodical exercise once in every year for getting the approval of the Appropriation Bill. But, this time, I have been stuck with one factor, namely, the huge increase in amount asked for approval. I mean, in earlier years, the amount asked for was much less. This time, it has gone up to the extent of Rs.30,942.62 crores! I am inclined to ask the well-informed, senior hon. Minister to check up whether a realistic estimate was made and whether correct calculations were done during the time of presentation of the Budget. Once a Budget is presented, only a marginal difference can be there between the main Budget and Supplementary Demands for Grants. But this time, I could see a huge increase in the amount. It can be checked up what are the areas on which the contingency was warranted to this kind of increase. Secondly, before I could make my observations, I am happy to note from the Economic Survey Report and other input that even the macrolevel global melt-down, the recession etcetera did not have that much effect on India. On the other hand, it has only a marginal effect.

3.00 P.M.

Even according to the Prime Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission. "It will have an effect on India. But it will have only a marginal effect."— this is what they have said. As it is, it has not done a great damage as it has done in other countries.

Sir, as far as the general economy of the country is concerned, the performance is better; the inflation is lower than the earlier year; the GDP growth is already there; the interest rate also is not that much. Then, the liquidity position and the flow of money in the banking system are quite satisfactory. Above all, the industrial growth and recovery havegained momentum; the resource mobilisation is very strong; the service sector growth remains at 8.5 per cent. What I am trying to say is, in the midst of these happy financial features and parameters, I am sorry to observe, that there are certain adverse effects also. Sir, as the Finance Minister is very well aware, the fiscal deficit has gone up by leaps and bounds. It could not have any control. Secondly, the agricultural production has fallen by 19 per cent; the rainfall has, again, fallen by 23 per cent; the trade is not faring well. On the other hand, the export has declined by 28 per cent; the import has also declined. Above all, — Sir, I repeat the words "above all" —the price-rise index has risen by leaps and bounds from one peak to another. I do not want to elaborate it because the Deputy Chairman will be pointing out that I have only five minutes!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Already, four minutes are over!

DR. K. MALAISAMY: The major income of a family or an individual goes to food and other consumer items only. This is the way the things are now happening. I can talk for half an hour to explain the effect of price rise that. But I stop with this. These are certain major adverse situations in spite of some happy features. This is there. It is the ground reality. In this connection, I would like to appeal to the hon. Minister to get over the adverse financial situation whether he can sustain the recovery of the economy, whether he can afford to sustain whatever is obtained now continuously. What are your measures and initiatives? Secondly, I would like to know whether you can afford to revive the export which has fallen. Thirdly, there are umpteen areas where you can invent and improve upon the domestic market.

Another important thing is that you have given a huge amount of money for so many schemes. The outlay is so big. We are very happy to see the figures. But what exactly is the outcome? This is where I want to talk for a minute. Whatever the schemes that you have, your leader, late Rajiv Gandhi, said that out of every rupee, only 15 paise or 16 paise reached the beneficiaries. In other words, 84 paise or 85 paise is spent by way of, or, absorbed by, the delivery mechanism, mostly by bureaucrats and other employees is. So, out of one rupee 85 paise or 86 paise go by way of spending on administration and bureaucracy and only 15 paise or 16 paise go to the beneficiaries. Where exactly the fault lies? To use my management language,

whether there is a system failure or human failure or the failure of both. According to me, there is something basically wrong in our implementation system. Your policy is right. Your idea is good. But your action is bad. That is why, whatever you want is not implemented. It is the ground reality.

Coming to the people below the poverty line, there are still 38 crores and out of ten pregnant women, nine women suffer from malnutrition or do not get nutrition. Forty-seven per cent of the children are undernourished. These are some of the areas where the economic level of the society is bad and they are poor.

Ultimately, I would like to emphasise that you have got your policy, programmes and other things. You kindly have a re-look at them. What is wrong with your policy? If your policy is right, the benefit should reach the beneficiaries. It does not reach them in reality. You think over what could be done. Thank you.

SHRI N. K. SINGH (Bihar): Thank you, Sir. When the hon. Finance Minister happily cut his birthday cake on his 75th birthday, a landmark event, there are more reasons for joy than merely the manufacturing sector index is looking up. He is one of the rare Finance Ministers who will be presiding over what can be called "a genuinely 'V' shaped recovery" for India because, I think, all indices appear to be that the recovery will be a sustained and a broad-based recovery. So, unlike other Finance Ministers in the world who bothered about an "L" shaped or "W" shaped or "U" shaped recovery, he will be presiding over, perhaps, a "V" shaped recovery and my congratulations to you, first of all, on that.

Being a Member of Parliament has many advantages, but some disadvantages too. One of the disadvantages is that an ordinary person influentially placed could, perhaps, have the privilege of being part of the pre-Budget consultations of the Finance Minister. The next time the House will discuss the economic situation, it will be the Budget time of the Finance Minister and we don't have the opportunity of giving him our pre-budgetary feedback. This is one of the disadvantage, therefore, being a Member of this august House. It is in this light that I have six suggestions to make to the Finance Minister. The first and foremost of them, I think, the Budget will, naturally, unravel a major area of tax reforms. My suggestion to you is that the Direct Tax Code, on which you are having wide-ranging consultations, I still feel, is still burdened with a number of infirmities. Please don't be in a hurry to rush with that Bill. Please try to synchronise the Indirect Tax Code and the Direct Tax Code and if you are in a position to have a comprehensive view of the nature of tax reforms which you would like to have...

...perhaps, you might consider setting up a bipartisan Tax Commission because taxation is not a partisan issue, to have a holistic look at the taxation, as a whole, before you begin to rush through ill-prepared, half-baked proposals on tax reforms. Pranab*da* you have enough time to

leave behind the Pranab legacy on tax reforms. So there need be no unseemly hurry in being able to push ill-prepared tax proposals when you present the next Budget.

Secondly, when you begin to present the next Budget, one of the things which will trouble you is the stimulus package. How should you sequence and exit from the stimulus package? Monetary first, fiscal first, pick up the excess of liquidity, suck out the liquidity in the system, or perhaps, do away with increased public outlays and curtail the tax which you have given! My suggestion to you is that go slow. You need to have a mid-point between the acquisition of being too fast and too soon or the other extreme of too late and too little. Find a middle way on the exit policy of your stimulus package in a manner where the incipient signs of recovery do not get hurt.

My third point is that if you look at the Indian economy as a whole, ironically speaking, the agriculture sector still gives only 16 to 18 per cent of your GDP, but livelihood to, perhaps, 58 to 60 per cent of the people. This is obviously an unsustainable situation. Manufacturing sector, as a whole, in this country has yet to take off and the growth impulse has largely come from the service sector. This is an unsustainable situation. What we like you to consider is how the manufacturing sector can get a genuine boost so that the downstream effects of employment growth in this country can leave behind a significant impact. If there is one lesson, which we can learn from China, is how to foster middle, low level skills which can give large employment creation, find gainful activity outside agriculture, create virtual circles around manufacturing hubs so that the services and the manufacturing sector growth can grow in tandem. This is something, Mr. Finance Minister, you may like to give some further thought to beyond the recommendations made and some very important recommendations made by the Committee on Competitiveness of the Manufacturing Sector.

My fourth suggestion to you, Sir, is on agriculture. Your colleague, I am sure, will impress upon you that the present spurt in prices is not a short-term phenomenon. This is because there are global factors, there are indigenous factors. So what can you do to improve short-term supply elasticity, improving the shelf life of products, giving a marketing chain and cold supply chain, improving rural connectivity, fostering an incentive structure which enables short-term responses to what may be a longterm endemic phenomenon?

My fifth point to you is, the Winter Session of Parliament is about to come to an end. Everybody knows that the Budget Session is primarily a Finance Bill Session and the Winter Session is primarily a Legislative Business Session. Fortunately, you might like to give some thought to a point made by Shri Prakash Javadekar that long pending legislations on important financial matters still remain mired either in the Standing Committees or in some form lie in limbo.

The advantage of having a Winter Session for a Legislative Business has been lost by the Government. You will, perhaps, have to consider how in your Budget Session, the Legislative Business of the Government can be blended along with your financial business.

My last point is that at a time when you present our next Budget, please take advantage of three important things. Take advantage of the Mid-Term Review of the Eleventh Plan on the contours of the draft outline of the Twelfth Plan, those making important suggestions. Secondly, take note of the recommendations likely to come before you from the next Finance Commission, whose term of office has been extended by three months. And also take note of some interim recommendations of the Commission on Centre-State Relations. Mr. Finance Minister, fortunately, for you the confluence, the conjuncture and the configuration, seem right. Do not prevaricate from taking those decisive steps which will decisively, indeed, make our economic recovery process a recovery process which is long-term, V-shaped process with sustained long-term economic growth, inclusive growth, low inflation and high employment. Thank you.

श्री अमर सिंह : सर, मैं आपके घंटी बजाने से पहले ही बैठ गया था और एक प्वाइंट भूल गया था। सर, मैं बोलना भूल गया था इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए 'ईगॉन' के चेयरमैन के रूप में दादा ने NTPC को प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, वह अभी भी चल रहा है विवाद में, न्यायालय में, शायद सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय ने NTPC के विरुद्ध, मैं 'कोपू' का निर्वाचित सदस्य हूं, इस बात की मुझे चिंता है कि NTPC के विरुद्ध एक affidavit दे दिया है। यह असत्य भी हो सकता है, अखबार की बात हर बार सच नहीं होती। अगर यह सत्य है तो मैं दादा का प्रोटेक्शन आपके माध्यम से चाहूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Janardhan Waghmare. Not present. Shrimati Vasanthi Stanley.

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu): Sir, thank you for giving me this opportunity to record my views on the Appropriation Bill (No.4) of 2009-10, for a total amount of Rs.30,942.62 crores, with the details of Supplementary Demands allocated to each Ministry over and above what has already been budgeted and approved by Parliament under the Union Budget in July. An overall view of the Supplementary Bill shows that the huge appropriations are made to the following Departments/heads. They are Pensions (Revenue), which amounts to Rs.4,533 crores, that is, 14.7 per cent of the total Appropriation; Department of Fertilisers, amounting to Rs.3,000 crores, that is 9.7 per cent; Department of Food and Public Distribution, Rs.3,660 crores, to the extent of 11.8 per cent; Defence Pensions, Rs.2,210 crores, to the extent of 7.1 per cent; Financial Services, Rs.1,266 crores, that is, 4 per cent; Department of Disinvestment, — it carries a lot — Rs.3,139 crores, that is, 10.1 per cent; Department of Urban Development, Rs.2,225 crores, that is, 6.5 per cent; and Others, amounting to Rs.11,109 crores, that is, 36 per cent. As we see it, the biggest demand is being made for Pensions and Disinvestment. Even when the whole world was trailing behind due to financial crisis, India was able to show a healthy 7.1 per cent GDP growth last year. But, this year, India is also slowly under the clutches of economic slowdown and financial crisis.

When I had the opportunity to register my observations over the Union Budget, I had said, "The Government seems to be counting on assumptions just to keep the fiscal deficit at 6.8 per cent of the GDP. The deficit is expected to be bridged by collection of increased direct taxes and so on. Without mentioning any specific target for public sector disinvestment, the Finance Minister has estimated to mop up Rs.1,120 crores during the fiscal year. I had also shared my concern that if any of the assumptions does not work out, the fiscal situation will get more precarious." But this is what exactly happened, Sir. Yesterday, the hon. Finance Minister stated in this House that there is a deep decline in indirect tax components and this is expected to be compensated with higher collection of the direct tax components in 2009-10. We, still, have lot of hopes on you, Sir, as a senior, experienced Minister, that you will come out with more plans and will take strict measures to collect the direct taxes, as well as, the left out indirect taxes, and, thereby bridge the gap more effectively and substantially.

I just have got two points more concerning my State, Tamil Nadu. The crop insurance due to the farmers is always shared in the ratio of 50-50 between the States and the Central Government. Due to the recent floods in Tamil Nadu, all the agricultural crops have been ruined. The Government of Tamil Nadu, immediately, compensated this by releasing their share of Rs.300 crores. We have to run from pillar-topost, from the Finance Department to the Agriculture Ministry and the Agriculture Insurance Company, but the Central Government is yet to give its share of Rs.300 crores. I also observe that only Rs.250 crores have been totally allotted for crop insurance. Leave alone Tamil Nadu, Sir, I request the Finance Minister to allocate more funds under this head and release the Central Government's share of Rs.300 crores towards crop insurance due for Tamil Nadu, and wipe away the tears of the farmers of Tamil Nadu.

My next concern is about compensation for VAT.

I reiterated this when I spoke on the Finance Bill. I again request you to recall, when VAT was introduced and the Government of India was insisting upon the State Governments to introduce it, the previous AIADMK Government was not willing to put itself to this acid test. Then, it was announced by the Central Government that the loss of revenue would be compensated. Hence, under the able leadership of our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. K. Karunanidhi, we had opted to introduce VAT by 2007. We should have been compensated to the extent of 100 per cent for the first year and to the extent of 75 per cent for the second year. We were compensated only to the extent of 75 per cent and 50 per cent respectively. The State Government had prepared the original Statement of Accounts to substantiate their loss of revenue, for compensation. The Central Government has not only not compensated fully but also tends to cross-check the accounts by way of A.G. audit which leads to inordinate delays. The same is the case so far as reduction of the C.S.T. from 4 per cent to 2 per cent is concerned.

Sir, Tamil Nadu is a manufacturing State and we also export to other States. We have incurred a loss in this regard. I request that pending compensation, which is more than Rs.1000 crores, should be released immediately to reinstate our faith and confidence in the Central Government. Our Chief Minister has taken up a lot of welfare measures. Sir, there is a sonnet by John Milton, 'On His Blindness' in which he says, 'Doth God exact day labour, light denied'. When he is blind, he is asking the God how He is expecting him to do all the work when he has denied him the daylight, that is, the eyesight. In the same way, I would like to ask the Central Government, if funds are not coming, then, how can we carry out our welfare measures. So, I request our Finance Minister to release all that is due not only to Tamil Nadu but to all other States. Sir, we are all very small and the Central Government is very big. I hope the Finance Minister will do the needful. Thank you, Sir.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : उपसभापति जी, सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ का जो प्रस्ताव माननीय प्रणब मुखर्जी जी लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं प्रणब बाबू को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जो global recession था, उसमें से सबसे पहले उबरकर आने वालों में भारत शामिल है। आज भारत ऐसा पहला देश है, जो इस मुसीबत से काफी हद तक निकल गया है। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर खत्म होने के कगार पर है, तब दुबई जैसे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ऐसी खबरें मिल रही हैं, जिनसे पूरा विश्व चौंक गया है। दुबई जैसा छोटा देश, जहां इतनी कंपनियां हैं, इतना पैसा है, इतनी तरक्की है, इसके बावजूद वह अपने आपको संभाल नहीं पाया, वहीं भारत जैसे विशाल देश के लिए जहां इतनी जनसंख्या है, इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके बावजूद इस स्थिति से निकालकर ले आना अपने आप में निश्चित रूप से सराहनीय बात है और हम सबको 7 प्रतिशत ग्रोथ की आशा भी बंधी है और 7 प्रतिशत ग्रोथ पर इस समय सरकार काम कर रही है, यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

उपसभापति जी, प्रणब बाबू जो प्रस्ताव लाए हैं, उसमें अगर एक-दो चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारे मित्र अमर सिंह जी ने एयर इंडिया की बात उठाई थी, एयर इंडिया और कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर इन दोनों के घाटे की बात छोड़ दी जाए, तो मोटे तौर पर जो पैसा है, वह जिन कामों के लिए आ रहा है, मेरे ख्याल से वे महत्वपूर्ण और उपयोगी काम हैं। उदाहरण के लिए जैसे नाभिकीय ऊर्जा, यूरेनियम खरीदने के लिए पैसा लिया जा रहा है, यूरेनियम के जरिए बिजली बनानी है, उस तरह के जो हमारे कारखाने हैं, उनके लिए पैसा लिया जा रहा है, धन आवंटित किया जा रहा है, फूड सब्सिडी के लिए दिया जा रहा है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए लिया जा रहा है, कर्ज़ माफी के लिए जो पैसा देना है, उसके लिए इसमें से धन लिया जा रहा है, सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर जो पेंशन दी जानी है, उसके लिए धन दिया जा रहा है, कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए धन दिया जा रहा है, मेट्रो रेलवे के निर्माण के लिए धन दिया जा रहा है और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स पर धन दिया जा रहा है। ये सारे काम ऐसे हैं, जो इस देश की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं।

इन मदों के खर्च के लिए अगर यह धन की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सबको इन मांगों का समर्थन करना चाहिए। एक बात महंगाई की आई। इसको प्रकाश जावडेकर जी ने उठाया और इस पर सारे लोग बोल गए। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है और महंगाई से सब चिंतित हैं। कांग्रेस अध्यक्षा बहुत चिंतित हैं, वह बराबर सरकार को बोलती रहती हैं कि इसके लिए प्रयास करने चाहिए। सरकार प्रयास भी कर रही है। यह महंगाई ज्यादा food items पर केन्द्रित है। यह essential commodities, जैसे खाने-पीने की चीजें, सब्जियां, आदि पर ज्यादा महंगाई है। इसकी वजह यह है कि खाद्य

पदार्थों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। यह कमी या तो आयात के जरिए पूरी हो सकती है या हमें अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार को जितना करना है, वह अपने ढंग से कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी लेनी पड़ेगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को भी इसमें सक्रिय करना पड़ेगा कि जो जमाखोरी वगैरह है, वह उसको भी रोकने की कोशिश करे। सब्जियों के दाम के लिए प्रधान मंत्री नहीं जिम्मेदार हो सकता है। सब्जियों के दाम के लिए कुछ जिम्मेदारी कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर को और मुख्य मंत्रियों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल स्तर की जितनी चीजें हैं, उन्हें इसको देखना पड़ेगा। पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम कर सकती है कि अगर किसी चीज की कमी है, तो उसको इम्पोर्ट करे। इम्पोर्ट की व्यवस्था को देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम हो सकता है, लेकिन अगर नीचे लेवल पर जमाखोरी हो रही है, तो उधर भी उन लोगों को आगाह करना पड़ेगा, उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो, उससे फ़र्क़ नहीं पड़ता है। एक ऐसा पक्ष जिसमें मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार थोड़ी कमजोर पड़ रही है, वह यह है कि राज्यों पर भी इसकी कुछ जिम्मेदारी डालनी चाहिए, जो हम बिल्कुल नहीं डाल पा रहे हैं।

श्री एन. के. सिंह ने Direct tax और Indirect tax के बारे में बात उठाई है। यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी इस पर लगातार लोगों से सलाह ले रहे हैं। लोगों के recommendations मंगा रहे हैं और Consultative Committee में भी यह काम चल रहा है। लोगों की और सब सांसदों की भी सलाह ली जा रही है। जीएसटी पर काफी अच्छे सुझाव भी आए हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड में काफी अच्छे सुझाव आए हैं। मैं श्री एन.के. सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि इस पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो निर्णय होंगे, ये बहुत लंबे वक्त तक चलने वाले होंगे। अगर कोई ऐसी नीति बनती है, जो कम से कम दस-बीस साल तक काम आए, उस दिशा में हमें ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो। टैक्स सिस्टम में जो जटिलताएं हैं, वे कम हों। टैक्स का जो बेस है, वह बढ़ना चाहिए, नेट बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों पर फोकस होकर उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते जाएं, उन्हें बढ़ाते जाएं, यह ठीक नहीं है, बजाए इसके कि हम नेट में विस्तार करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर लाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं किसी खास प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वकीलों का है, जो जिला स्तर पर वकील हैं, वे बुरे हाल में हैं। जो तहसील स्तर पर वकील हैं, वे बुरे हाल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की अंधाधुंध कमाई है, लेकिन individuals के नाम पर सर्विस टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वह कंपनी पर लगता है। कोई वकील कंपनी बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं, जैसे सालिसीटर फर्म और लॉ फर्म, आदि बनाते हैं। हमारे रवि शंकर प्रसाद जी बैठे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने कंपनी बनाई या नहीं बनाई। वह बुरा मान रहे होंगे। वह मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं, लेकिन यहां तो देश हित में बात करनी है ..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : महोदय, यह व्यक्तिगत मामला सदन में नहीं उठना चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री अमर सिंह : महोदय, यह साले बहनोई का रिस्ता है ..(व्यवधान).. दोनों ने मिल कर बांट लिया है..(व्यवधान).. इनके दोनों हाथ में लड्डू है ..(व्यवधान).. एक इधर है और एक उधर है..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : प्रणब बाबू से मैं मांग करता हूँ कि रवि शंकर जैसे व्यक्ति पर, भले ही वे रिश्तेदार हों, सर्विस टैक्स लगनी चाहिए..(व्यवधान)..

SHRI Y.P. TRIVEDI (Maharashtra): Sir, they are not paying service tax because they are not rendering any service. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव शुक्ल : ऐसे लोगों पर तो सर्विस टैक्स लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी उसमें आते हैं, तो मैं क्या करुं। देश हित की बात करनी चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री रवि शंकर प्रसाद : पत्रकार पर भी सर्विस टैक्स लगनी चाहिए ..(व्यवधान)..

श्री राजीव शुक्ल : पत्रकार तो देते ही हैं ..(व्यवधान)..। उसके लिए तो हम तैयार हैं। इस समय जो स्थिति है, जो इन्होंने ब्योरा दिया है, उसमें indirect tax में 7.5 परसेंट का decline है। मेरा यह मानना है कि उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट टैक्स पर जोर देकर, वहां पर शक्ति करके, वहां से वसूल कर इस कमी को पूरा किया जाए। यह ठीक नहीं है। Indirect tax को कैसे बढ़ाया जाए, इसके उपाय खोजने चाहिए। मैं यह एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ।

महोदय, लिक्विडिटी को लेकर आज बात हो रही है कि जिस तरह से पांच से छः परसेंट महंगाई दर बढ़ने की बात है, तो शायद रिज़र्व बैंक, मार्केट से लिक्विडिटी को withdraw करे। मुझे नहीं लगता है कि यह करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। आप जिस तरह से recession को खत्म करने में कामयाब हुए हैं, उसकी एक वजह यह है कि आपने लिक्विडिटी को मार्केट में डाला और उसके असर देखने को मिले। अगर उस liquidity को फिर वापस खींचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका वह purpose पूरा हो पाएगा, फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए।

सर, केंद्रीय योजनाओं की monitoring एक बहुत important चीज़ है। भारत सरकार विकास योजनाओं के लिए इतना पैसा देती है कि अगर वह सचमुच उपयोग हो, तो गांव सोने के हो जाएं ! आज ये देहात न रहें, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह हमारे गांव हो जाएं, लेकिन समस्या यह है कि वह पैसा वहां लग नहीं पाता है। तो इसलिए साठ साल बाद, अब केंद्र सरकार को कोई न कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और प्रणब बाबू जैसा वित्त मंत्री ही वह बना सकता है कि केंद्र सरकार का पैसा, उसकी direct monitoring Government of India करे, उनकी एजेंसियां करें। अगर सी.बी.आई. लगानी है, तो इन पर लगाओ। ये पांच-पांच सौ रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ते घूम रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। भारत सरकार का हज़ारों करोड़ रुपया, जो निचले लैवल पर सफाचट होता है और आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता, गांवों तक पहुंच नहीं पाता, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, ये एजेंसियां वहां काम करें, वहां direct monitoring हो, बजाय इसके कि कुछ individuals को पकड़ते घूमें। अगर हमने वैसा कर लिया, तो हमें उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई Monitoring Department होना चाहिए, जो Government of India के एक-एक पैसे की monitoring करे कि वह सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। आप अपने काम की इतिश्री इससे नहीं समझ लीजिए कि आपने पैसा भेज दिया और राज्य सरकारें चाहे जैसे उसे खर्च करें, चाहे वे उसकी तनख्वाहें बांट दें, चाहे इधर का पैसा उधर कर दें। किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, Central Government के पैसे की monitoring direct Central Government के हाथ में होनी चाहिए, यह सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

सर, अब मैं employment के बारे में कहना चाहूंगा कि employment एक बड़ी जबरदस्त समस्या होने जा रहा है, क्योंकि रोज़गार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं। मैं एन.के.सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि manufacturing sector पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चीन ने manufacturing sector" के सहारे ही grow किया है। हमारे यहां सर्विस सेक्टर बढ़ता चला रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन manufacturing sector" के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा पैकेज बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ राहत उन्हें ऐसी देनी पड़ेगी कि जब तक इस देश में उद्योग-धंधे नहीं लगेंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी और उन्हें बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए।

सर, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि recession का आखिरी दौर है, नाव बिल्कुल किनारे पहुंच गई है और अब नाव को देखना है कि कहीं डूबने न पाए, इसलिए सरकार को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। अगर

एकाध कोई stimulus package की जरूरत पड़े, stimulus package not in terms of money, तो मैं कहता हूं कि अगर पॉलिसी लैवल पर रिलीफ देकर कुछ हो सकता है, तो देना चाहिए, ताकि पूरी तरह हमारा बेड़ा पार हो सके और हम किनारे पहुंच सकें, यही वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है, बहुत- बहुत धन्यवाद।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने सोचा था कि देश के एक senior politician देश के वित्त मंत्री बने हैं, देश के 5th Schedule Area में जो Tribal Area Sub-Plan है, उसके लिए वित्त मंत्री महोदय एक स्पेशल पैकेज या स्पेशल प्लानिंग बनाएंगे, आज के हिंदुस्तान में सबसे दयनीय अवस्था में जो गरीब तबके के शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ रहते हैं, उनके बारे में कोई नई योजना बनाएंगे, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आज़ादी के 62 साल बाद भी जितने Tribal Area Sub-Plan हिंदुस्तान में हैं, उनमें जो आम जनता रहती है, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़, ओ.बी.सी. और other population, जो लोग भी रहते हैं, वे आज भी economically, educationally, socially, देश की आज़ादी से पहले जैसे थे, आज भी उसी तरीके से रह रहे हैं। आप जब तक उन tribal pockets में जाकर नहीं देखेंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे। जैसा आपके आंकड़े बताते हैं, शेड्यूल्ड एरिया को छोड़िए, रूरल इंडिया में झारखंड में 54.2 परसेंट एस.टी. below poverty line हैं । एस0सी0 57.9 परसेंट below poverty line में हैं, ओ0बी0सी0 42.2 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स रूरल एरिया में 37.1 परसेंट below poverty line में रह रहे हैं। उसी हिसाब से अर्बन इंडिया में एस0टी0 41.1 परसेंट below poverty line में हैं, एस0सी0 47.2 परसेंट below poverty line में हैं, ओ0बी0सी0 19.1 परसेंट below poverty line में हैं और जो अदर्स हैं, उनका थोड़ा डेवलेपमेंट हुआ है, 9.2 परसेंट below poverty line हैं।

उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में एस0टी0 75.6 परसेंट below poverty line में हैं, एस0सी0 50.2 परसेंट below poverty line हैं और ओ0बी0सी0 36.9 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स 23.4 परसेंट below poverty line उड़ीसा के रूरल पॉकेट में हैं। उड़ीसा के अर्बन एरिया में एस0टी0 61.8 परसेंट below poverty line हैं, एस0सी0 72.6 परसेंट below poverty line हैं, ओ0बी0सी0 50.2 परसेंट below poverty line हैं और अदर्स 28.9 परसेंट below poverty line हैं और ऑल इंडिया below poverty line is ..**(समय की घंटी)**..

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) : हो गया।

श्री मंगल किसन : सर, हम कभी नहीं बोलते हैं। आप दो मिनट का समय और दे दीजिए। ऑल इंडिया एवरेज 27.5 परसेंट below poverty line है। हम लोगों का जो भी सब-प्लान एरिया है, कमोबेश उनकी हालत इसी प्रकार से है। जब हम आजादी के 62 साल के बाद भी, वहां के लोग जैसे पहले रहते थे, आज भी हम वहां के लोगों को उसी हिसाब से रखेंगे, तो यह देश के लिए और समाज के लिए सबसे दुख की बात है। इसीलिए मैं सब-प्लान एरिया के लिए हाथ जोड़कर माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसे नार्थ- ईस्ट के लिए पैकेज बनाया गया है, कम से कम उसी तरह का पैकेज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बाकी बिहार और अन्य राज्यों में जो पाट्र्स एरिया है, उनके लिए स्पेशल प्लानिंग एवं प्रोग्राम बनाने की कृपा करें। ..**(समय की घंटी)**..

सर, हम आदिवासी लोग जो भाई-बहन हैं, हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है। जैसे फ्लड आने पर, हाउस डैमेज होने पर आप इंदिरा आवास लोगों को देते हैं, कम से कम कुछ नहीं होने से देश में यह जो ट्रायबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट हैं, उनको इकट्ठा देने से, जम्बलिंग करके देने से, वे लोग अपने राइट को अवेल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से और सरकार से अनुरोध है कि पिछड़े राज्यों के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए इंदिरा आवास देने के लिए स्पेशल प्रॉविजन करने की व्यवस्था की जाए। मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Trivedi. Please take only three minutes.

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, I am replacing Mr. Waghmare who is not here. But I will take very little time.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Waghmare always sticks to time. He is reputed for that.

SHRI Y.P. TRIVEDI: He has stuck to the time by not remaining present. Sir, first of all, I would like to join the chorus of praise which is bestowed on the Finance Minister. He is such a mature man, such a dignified man with so much resoluteness. It was said about Disraeli that when he used to move out, people used to look at his composure, people used to look at the confidence on his face and they used to feel that there is total political stability in the country. In the same way, the moment people see the confidence of our Finance Minister; it is so contagious that to a certain extent the economic recovery is due to the composure and the way in which he has behaved himself. I confine myself only to two items because the time at my disposal is very short. The first is the Direct Tax Code which was initially the 1922 Income Tax Act. It lasted for about 40 years and in 1961 the new Income Tax Act was heralded as a measure for simplifying and rationalising the tax structure. It ultimately turned out to be the most complicated piece of legislation. There were explanations which were mounting on provisos, provisos which were mounting on explanations and there was not a single section which could stand by itself. It was always over-lapping another section and very often so many sections used to say, 'not withstanding anything contained in any other part of the Act'. So we would not know which one will stand and which one would go. So, that was a sort of a cobweb. From that we had to come out. So, we have the Direct Tax Code. A lot of confidence is reposed by people, the tax payers, the tax gatherers, the tax advisers. All are looking at the Direct Tax Code and it has to be brought in the Statute Book as early as possible but there are so many infirmities in the Act. One of them is the Minimum Alternative Tax. The Minimum Alternative Tax was conceived as a tax when so many companies used to earn money, earn profits, used to pay dividend but were not paying tax. So, there was a Minimum Alternative Tax. Now, that tax has been brought out in the Direct Tax Code as a measure that even if the company is making a loss, still it has to pay the tax because now it has to be joined on the gross value of the asset, not on the profitability. This is ununderstandable.

The tax on the gross value of assets actually means the wealth tax. It is not an income tax. In spite of the fact that there may not be any income still the tax has to be levied. I think, it is very high time that this code which is coming should be given to the Select Committee. The Select Committee should move to the various centres to find out the voice of the trade associations, the professional bodies and should come out with concrete suggestions and the tax code should come as early as possible. It should not be delayed because the present Act is unworkable. The

second point which I would like to urge upon is the plight of Mumbai. Mumbai, as it is said, contributes almost one-third of the Direct and Indirect Taxes of the country. But, still Mumbai has been denied. When I come to Delhi and when I look at the contrast between Mumbai and Delhi, I am pained because Mumbai has no infrastructure. Even sometimes commuting to a distance of about one kilometre or two kilometres it takes half an hour or one hour. The infrastructure is totally ruined. There is no metro. Commutation is so difficult. Housing has gone to a level which is ununderstandable. As I said, in one of the occasions, a square foot of area can fetch as much as Rs. one lakh. That is the plight of housing in Mumbai. I think something should be done. A large part was promised to be given to Mumbai for the purpose of development but it has not come. I think Mumbai is lagging behind. I am afraid Mumbai will become a dying city and as early as possible funds should be earmarked for Delhi, for Mumbai and some scheme should be evolved to see how these funds are to be utilised in Mumbai.

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर) : सर, सबसे पहले तो मैं जनाब वजीरे ख़ज़ाना को अपनी जमात की तरफ से और अपनी तरफ से मुबारकवाद पेश करता हूँ कि इन्होंने निहायत ही मुश्किल हालात में मुल्क की मइशियत को इस्तेहकाम दिया और जो सारी दुनिया में एक तरह का बोहरान था, अपने मुल्क को उस बोहरान से बचाया। Supplementary Financial Bill, जो इस वक्त एवान के सामने है और जिस पर बहस हो रही है, यह दरअसल जो बजट पास हुआ है, उसमें जो मुख़्तलिफ महकमाजात थे, इखराजात में इजाफा होना, उस इजाफे को पूरा करने के लिए इन्होंने यह बिल लाया है। बजट इजलास के दौरान भी मैंने अपनी रियासत के हवाले से कई मामलात इनकी नोटिस में लाया था। आज भी दो-तीन मामलात, जो निहायत ही अहम हैं, अमन और सलामती के लिहाज से भी और रियासत जम्मू-कश्मीर की मजमूई तरक्की के लिहाज से भी, मैं इनकी नोटिस में लाना चाहता हूँ।

गुज़िश्ता 15 साल से एक बड़ा मामला मरकज़ी हुकूमत के सामने रहा। वह है रजौरी-पुंछ-बारामूला-कुपवाड़ा और दूसरे सरहदी इलाकों में रहने वाले पहाड़ी लोगों का मामला। उनका यह मुतालबा रहा है और वक्तन फोक्तन जितनी भी हुकूमतें गुजिश्ता 15 वर्ष में बरसरे इक्तिदार यहाँ पर रहीं, उन्होंने एवान में भी और एवान से बाहर भी इस मामले पर हमदर्दाना गौर का वादा किया। मसला है पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले लोगों को दर्द-ए-फरिश्त कबायल के जुमरे में शामिल करना, उनको ST status देना। कई बार इस ऐलान में भी इस मसले पर मुबाहिसे होते रहे। इससे पहले भी जो वजीरे आजम आए हैं, उन्होंने भी इस बारे में हमदर्दाना गौर का यकीन दिलाया और अब भी वजीरे आजम ने इस मसले पर कुछ फैसला करने का यकीन दिलाया। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस ऐवान में यह बात बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ी लोग हमारे सरहद और Line of Actual Control के आसपास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। अगर एक ही गाँव के एक हिस्से और एक ही तरह के समाजी और इक्तिसादी हालात में रहने वाले लोगों के हिस्से को आप Scheduled Tribe करार दें और समाज के उस दूसरे हिस्से को महरूम रखें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महरूमी का क्या आलम हो सकता है। इसलिए बेचैनी बढ़ रही है, बेचैनी मौजूद है। इसके निहायत ही मनफी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। यह सारा पहाड़ी इलाका है और निहायत ही हस्सास इलाका है अमन, सलामती और दिफा के लिहाज से। मेरी

यह गुजारिश होगी कि आप इस मामले पर फैसला करवा दें, ताकि आबादी के एक बड़े हिस्से को जो उनका एक मुतालबा रहा है, उस मुतालबे को पूरा करवा कर इस बेचैनी को दूर करें।

दूसरा एक बड़ा मामला है। 1996 से लेकर 2002 तक मैं खुद अपनी रियासत का वजीरे तालीम भी रहा। उस वक्त एक प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था पॉलिटेक्निक को जदीद बनाने का, वुसअत देने का और उनके मयार को ऊँचा करने का। **(समय की घंटी)** सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए, सरहदी रियासत के मामलात हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : पाँच मिनट हो गए, मैं क्या करूँ। मैंने तीन मिनट कहा था, आपने पाँच मिनट लिया।

श्री मोहम्मद शफ़ी : सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, मेरी आपसे गुज़ारिश है। तब तो वर्ल्ड बैंक ने रुकुमात मंजूर किए और हमने उस प्रोजेक्ट पर अमलावरी भी की। अब भी वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और वह है Ministry of Environment and Forest का Watershed Development Programme. उसके लिए जो तमाम लवाज़मात जरूरी थे, वे मंजूर हो गए हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक से उसके लिए रूकुमात आने हैं, वह अभी तक नहीं आए हैं। इसमें यह बात कही जा रही है कि शायद इस रियासत के स्टेटस पर एक सवालिया निशान फिर दोबारा इस बेनुलअकवामी सतह पर आ गया है और इसीलिए वर्ल्ड बैंक पैसा मंजूर नहीं कर रहा है। मैं वज़ीरे ख़ज़ाना से गुज़ारिश करूंगा, बहुत सारे अंदेशेहाय उन दूर दराज़ के लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं। फोरी तौर पर वह इस पर तवज्जुह दें और जो फंड्स वर्ल्ड बैंक के पास रुके हुए हैं, उनको वह वागज़ात करवाएं ...(व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are other businesses to be taken up.

श्री मोहम्मद शफ़ी: तीसरा बड़ा मामला जो हमने लिया है ...(व्यवधान)।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी.जे. कुरियन): शफ़ी जी, आपका टाइम खत्म हो गया है।

श्री मोहम्मद शफ़ी: बस एक बात को और कहने दीजिए। जब गुज़िश्ता बहस हो रही थी, तब भी मुझे बोलने के लिए तीन ही मिनट मिले थे। वह इस रियासत में unemployment का मसला था। मैंने तब भी यह बात कही थी और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं कि unemployment के लिहाज़ से जब तक आप कोई स्पैशल पैकेज नहीं देंगे, तब तक यह खत्म नहीं होगी। रियासत ने तो अपने तौर पर एक स्पैशल पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन वसायल के न होने की वजह से उस पर अभी पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है, उसके लिए भी यह कहा गया है कि अप्रैल तक हम इस पर अमलावरी शुरू करेंगे।

मैंने पिछले बजट इजलास में भी यह बात कही थी और मरकज़ी हुकूमत के जितने भी अदारे हैं, उनसे आज फिर मैं यही गुज़ारिश करूंगा कि आप रियासत के नौजवानों को, वे जिस-जिस काबलियत के हों, इंजीनियर से लेकर बाकी सब तक, उनको एक स्पैशल पैकेज के ज़रिए employment फराम करें ...(व्यवधान)।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We have to take up other businesses. आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद शफ़ी: उससे ऐतमाद भी बढ़ेगा और जो एक बेचैनी का आलम पांच लाख बेरोज़गार पड़े नौजवानों में हैं ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, okay. *(Time-bell rings)*

श्री मोहम्मद शफ़ी: उनके दिल में एक इत्मिनान पैदा हो जाएगा। अमन और सलामती को कायम करने के लिए यह पैकेज मरक़ज़ी हुकूमत की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। बहरहाल शुक्रिया।

جناب محمد شفیع (جموں اور کشمیر) : سر، سب سے پہلے تو میں جناب وزیر خزانہ کو اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت ہی مشکل حالات میں ملک کی معیشت کو استحکام دیا اور جو ساری دنیا میں ایک طرح کا بحران تھا، اپنے ملک کو اس بحران سے بچایا۔ Supplementary Financial Bill, جو اس وقت ایوان کے سامنے ہے اور جس پر بحث ہو رہی ہے، یہ دراصل جو بجٹ پاس ہوا ہے، اس میں جو مختلف محکمہ جات تھے، اخراجات میں اضافہ ہونا، اس اضافے کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے یہ بل لائے ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران بھی میں نے اپنی ریاست کے حوالے سے کئی معاملات، ان کے نوٹس میں لایا تھا۔ آج بھی دو-تین معاملات، جو نہایت اہم ہیں، امن اور سلامتی کے لحاظ سے بھی اور ریاست جموں-کشمیر کی مجموعی ترقی کے لحاظ سے بھی، میں ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔

گزشتہ 15 سال سے ایک بڑا معاملہ مرکزی حکومت کے سامنے رہا، وہ ہے راجوری-پونچھ-بارہمولہ-کپواڑہ اور دوسرے سرحدی علاقوں میں رہنے والے پہاڑی لوگوں کا معاملہ۔ ان کا یہ مطالبہ رہا ہے اور وقتاً فوقتاً جتنی بھی حکومتیں گزشتہ 15 سالوں میں برسراقتدار یہاں پر رہیں، انہوں نے ایوان میں بھی اور ایوان سے باہر بھی اس معاملے پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ مسئلہ ہے پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کو درد فرشت قبائل کے زمرے میں شامل کرنا، ان کو ایس-ٹی۔ اسٹیٹس دینا۔ کئی بار اس اعلان میں بھی اس مسئلے پر مباحثے ہوتے رہے۔ اس سے پہلے بھی جو وزیر اعظم آئے ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں ہمدردانہ غور کا یقین دلایا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ایوان میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑی لوگ ہمارے سرحد اور Line of Actual Control کے آس پاس رہتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر ایک ہی گاؤں کے ایک حصے اور ایک طرح کے سماجی اور اقتصادی حالات میں رہنے والے

[ ] Transliteration in Urdu Script.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There are other businesses to be taken up.

جناب محمد شفیع : تیسرا بڑا معاملہ جو ہم نے لیا ہے ...(مداخلت)...

اپ سبھا ادھیکش : شفیع جی، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔

جناب محمد شفیع : بس ایک بات کو اور کہنے دیجئے۔ جب گزشتہ بحث ہو رہی تھی، تب بھی مجھے بولنے کے لئے تین ہی منٹ ملے تھے۔ وہ اس ریاست میں ان-ایمپلانمنٹ کا مسئلہ تھا۔ میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی اسی بات کو دوہرا رہا ہوں کہ ان-ایمپلانمنٹ کے لحاظ سے جب تک آپ کوئی اسپیشل پیکیج نہیں دیں گے، تب تک یہ ختم نہیں ہوگی۔ ریاست نے تو اپنے طور پر ایک اسپیشل پیکیج کا اعلان کیا ہے، لیکن وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ابھی پوری طرح سے عمل نہیں ہوا ہے، اس کے لئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپریل تک ہم اس پر عمل آوری شروع کریں گے۔

میں نے پچھلے بجٹ اجلاس میں بھی یہ بات کہی تھی اور مرکزی حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان سے آج پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ ریاست کے نوجوانوں کو، وہ جس جس قابلیت کے ہوں، انجینئر سے لیکر باقی سب تک، ان کو ایک اسپیشل پیکیج کے ذریعے ان-ایمپلانمنٹ فراہم کریں ...(مداخلت)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We have to take up other businesses. آپ سماپت کیجئے۔

جناب محمد شفیع : اس سے اعتماد بھی بڑھے گا اور جو ایک بے چینی کا عالم پانچ لاکھ بیروزگار پڑے نوجوانوں میں ہیں ...(مداخلت)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, okay. *(Time-bell rings)*

جناب محمد شفیع : ان کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لئے یہ پیکیج مرکزی حکومت کی ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ بہرحال شکریہ۔

(ختم شد)

[ ] Transliteration in Urdu Script.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, first of all, I would like to express my gratitude and appreciation for the observations made by the hon. Members. When we have the opportunity of discussing supplementary demands, it provides us an opportunity to have an overall review of the economy and also to point out whether it is going in the right directions, or, there are certain deviations and deficiencies. Some hon. Members have pointed out; I will just point to that. Some hon. Members have also come out with very constructive and positive suggestions and, in fact, most of them have done so. They have critically analysed various proposals and found the justifications for the demands for supplementaries. The Economic Policy is to be analysed, of course, in the context of political philosophy or economic philosophy of a political party. Nothing wrong or unusual in it, but, at the same time, it will have to be placed in the context of the contemporary ground situation in which the Economic Policies are formulated. It cannot be in abstract and in isolation of the ground reality.

First of all, if somebody suggests that the economy is going down, what are the criteria, what are the parameters? Sir, on all the four major parameters — economic growth, tax-GDP ratio, fiscal deficit and debt-GDP ratio — Indian economy has withstood. When you judge the economy of a country, you cannot judge it in four months, five months or six months or even in one year context. You will have to evaluate the performance of the economy, at least, over a medium-term policy. If we look at the fiscal deficit, in the five-year period between 1999 and 2004, the fiscal deficit was 5.5 per cent of the GDP. It has been brought down to 3.58 per cent in the next four years. Therefore, the economy is improving; economy is not going down. If you want it year-wise, I also have the year-wise figures but to save the time of the House, I am not quoting that. Now, if we take into account the overall GDP growth, India did never have 8.6 per cent GDP growth over a compact period of five years. You take the entire period of the Plan development from 1951 onwards. During 1951-79, the GDP growth was 3.5 per cent. In the entire 80s, from 1981-1990, it was 5.5 per cent. In the fist half of 90s, it was 5.6 to 5.7 per cent; in the second half of the 90s, it was around 6 per cent and up to 2003-04, it was 6.7 per cent. So, we have achieved a growth rate, over a period of five years, of 8.6 per cent.

Now, if you look at Central Government debt to GDP ratio, yearwise, from 1999 till date, particularly, from 1999 to 2003-04, this five-year period, it was around 63 per cent; some time, it was 63.5 per cent, some time, it was 63 per cent; some time it was 62.2 per cent and now in the last two years, it has been brought down to 60 per cent I am talking of the Central Government's debt-GDP ratio, not the country's economy as a whole because in States, there would be variation, but not much.

Therefore, in all these three major parameters, the Indian economy has done well over a period of last five-six years. Everybody knows, all over the world, that 2008-09 is an

extremely difficult year and 2009-10 will also be equally difficult year. The world is still grappling to come out of the situation, come out of the worst recession since 1930s of the last century. We are not living in isolation. We are not in cocoon. Whatever happens in the world has its own impact. There is no mechanism by which we can insulate ourselves from the adverse impact of the world's development.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

If our exports go down, any number of speeches here or economic discourses are not going to improve the performance on international trade, when we know that 62 per cent of our exports are destined to North America, Europe and Japan, and if there is not a robust economic recovery and generation of demand, Indian export cannot come to the level of 33, 34 or 35 per cent, which we were having in the pre-meltdown situation. If the manufacturing sector has gone down, naturally, the indirect tax revenues will come down. Somebody said that we have provided a stimulus to help capitalists to the extent of Rs.4,88,000 crores. It is not Rs.4,88,000 crores but Rs.1,86,000 crores, and the entire package is not meant for industrial revival. A substantial part of it was meant for generating demand and to step up the developmental expenditure in one year, between 2008-09 and 2009-10; developmental expenditure has been increased by Rs.40,000 crores, from Rs.2,85,000 crores to Rs.3,25,000 crores, between BE to BE, with the hope and expectation that when demand generation in the advanced economies of the world is not taking place, let us make efforts to generate demand internally. And, that strategy has paid off. As we have noticed, in the first quarter, our GDP grew by 6.1 per cent during April, May and June. Then, in the second quarter of July, August and September, it was 7.9 per cent; taken together in the first two quarters, in the first half of the year, it is seven per cent. And what was the performance immediately before this in the previous two quarters? It was 5.7 and 5.8 per cent of GDP. Therefore, it is slowly moving. It is not that everything is absolutely perfect; nobody claims that. No growing economy can be perfect. There will be deficiencies. There will be shortcomings. And we shall have to try to overcome these deficiencies and shortcomings.

On economic issues, there will be different perceptions; there is no doubt about that. In a multi-party system, in a multi-party democracy, there will be divergence of views. But, over the years, we have been able to bring some sort of convergence. As it was pointed out, when you introduced economic reforms in the early '90s, I had the privilege of being in the Government even at that time. And at that time, I was a Member of this House. Sitting in this House, I witnessed how the different perceptions were placed. But when a major political party came to power, they not only accepted that policy, but in their own way, they gave a momentum to it. I do agree, and that would be the continuity. The other day, when I was replying to the discussion on disinvestment, most humbly and respectfully I had pointed out that from 1991, there had been three formations till date.

4.00 P.M.

Congress was there. Congress is now along with other partners. From 1991 to 1996, the Congress Party ruled this country alone. From 2004 till date, it is heading a coalition, and, before that, there were two terms of NDA. In between, there were elections, and, prior to that, there was another combination consisting of certain other political parties, supported by us and also supported by the Left, and, they also ruled. But, disinvestment continued from 1991 onwards. It has been pointed out; I do agree — the other day, I was quoted — and, I do believe that the disinvestment proceeds should not be used to meet the normal revenue consumption expenditure. It should be used as we are disposing of capital assets, part of it; it should be used for creation of additional capital assets. There is no doubt about it. What is the concept of the NIF, the National Investment Fund? The amount will not be deposited in the Consolidated Fund. What I have stated in the Supplementary Demands is an exception.

In the other House, while replying to the debate, I said, again, we will go back, from the 1st of April, 2012 to deposit in the NIF. Main corpus will remain intact and the income earned out of the corpus will be used for the social sectors, and, three social sectors have been identified. One social sector is 'Health', another social sector is 'Education', and, the third social sector is 'Employment Generation'. These are the projects; these are the targeted social sectors where some investment will be made. But the fund has been operated recently. Up to now only 1800 crore of rupees have come, and, from there, the corpus which was created, in the first year, we got about 84 crore of rupees, and, in the second year, we got about 250 crore of rupees, with the corpus remaining intact. Each investment — which I have indicated in the supplementary, both on the receipt side and on the debit side — that we are to take in is by making an exception. Because of the extraordinary situations, I have to burst the ceiling of the normal fiscal prudence. I myself admitted in the Budget that 6.8 per cent fiscal deficit is not sustainable. We cannot sustain it. Then, we shall have to go back to the situation of 1991, when to borrow a few hundred million dollars, we had to pledge our gold to the Bank of England. I do not want to have that situation. Therefore, the fiscal prudence must be maintained. Sir, 6.8 per cent fiscal deficit cannot be maintained, and, that is why, I have indicated, in my Budget speech itself, that very soon, I would like to come back to the normal fiscal prudence. I have also indicated that the fiscal deficit in the year 2010-11 will be 5.5 per cent, and, in the year 2011-12, it will be 4 per cent, and, thereafter, we shall have to come back to 3 per cent. Because of the intensity of the meltdown, it will take some time, and, in the Indian economy, it will not be less than two to three years. That is why, I have taken this much time.

I come to the third point, and, I want to say something in response to some very valuable suggestions. For instance, on the consultation with the MPs, what I am going to do is that I am

going to have the meeting of the Consultative Committee attached to the Finance Ministry, and, in that pre-Budget meeting of the Consultative Committee, I will not speak, I will invite the Members to give their suggestions on what according to them should be incorporated in the Budget proposals.

I am going to start this exercise from now, apart from the various other groups which we are meeting. I have introduced the system of having interaction with the State Finance Ministers. In fact, I will start meeting with them. From the 15th of January, I will have the meeting with the State Finance Ministers and thereafter with other various groups, economists, industrialists, trade unions, farmers' interests, etc. So, I will have them.

Now, another important suggestion has come about the direct taxes and the GST. I have stated earlier, and I am repeating it, I am with an open mind. I want major tax reforms. But I am not in a hurry to do something that instead of doing good, it will make the situation worse. I want improvement. I want to do something better than what we have today. Therefore, to replace the existing Income Tax Act which, as has been correctly pointed out in 1922, in 1961 and thereafter so many amendments have taken place that the original shape of the Income Tax Act has been modified so much that sometimes we lost the alphabets and go on adding to it. Therefore, it should be a new code. It will not be the amendment to the 1961 Act. It will be the new code and it would incorporate certain important segments. We are having interactions with various stake-holders. Definitely, after it is introduced, it will be the job of the House to decide how it will respond to it and I will have that.

Mr. Rajeev Shukla raised one issue, a very pertinent one, as I mentioned in my introductory observations that though there would be 25,000 crores of rupees, 30,000 crore rupees I have projected. But as I have explained, 5,000 crore rupees is net savings and 0.73 crores are technical supplementary. So, the net cash outgo would be 25,000 crore rupees. But still, I am not worried over it because there will be some savings in certain other heads. But as the supplementary demands are not from those heads, I could not square it out. I had to spend but in other heads, there will be some savings. So, the net outgo, I am hoping, as a result of the first supplementary, would be zero. I explained yesterday on which heads we have had it.

Certain other important issues have been raised. Mr. Malaisamy raised the question that where you have such a hefty 25,725 crores of rupees as supplementary demands. It is true that sometimes the supplementary demands have been 1 per cent, 1.5 per cent or 2 per cent. This time it is 2.5 per cent of the total Budget. It is a little more. But it is not absolutely exceptional because in the previous first supplementary Budget, it was more than 1,00,000 crore rupees, 1,05,613 crore rupees. So, compared to 1,05,613 crore rupees, my first supplementary is much less; it is 25,000 crore rupees. So, sometimes it has been 5 per cent; sometimes it has been

6 per cent. It has been depending on the situation. And, it is not correct that we did not make the realistic assessments. Please remember that in our Budget-making systems, it will have to be estimated because when I will arrive at the final figure and present to you on the last working day of February, the figures which will be available to me, the actual figures, would be relating to the month of December, at best, relating to the month of January. I have to estimate the figures for the two months of the current financial year — what would be the revenue receipt; what would be revenue expenditure; what would be capital receipt; what would be capital expenditure; all will have to be estimated on pro rata basis that is up to December or January I have received so much. So, in the month of February, in the month of March, I expect to have it. It will be estimated. Therefore, there will always be a grey area. That is why, in our Budget document, we always give Budget Estimates and Revised Estimates. When the actuals are available for one year, in one document you will find actual B.E. and R.E. We have these inherent handicaps and we have to cope with it. But the system has been accepted.

I will give you just one example of it. It has been raised by Shri Amar while speaking on the Air India. It is true that everybody has this doubt whether this package of Rs.800 crore is one-time go, or, whether it will be continuing. What is actual loss? Loss is substantial. But this package of Rs.800 crore came after the recommendations of a Group of Ministers which was set up to look into the health of the Air India. The Group of Ministers while analysing the package arrived at a decision that this much amount might be given to them. But it could not be anticipated when I presented the Budget on 6th of July, because all these developments took place later on. Similar is the case in certain other areas. For instance, import of fertilizers, urea. For instance, pension for defence personnel. I have to enhance it substantially, because after the Pay Commission's Report, there were various anomaly committees at the level of officials. There were some costs. One major thing took place. We have made some substantial improvement in the pension of our *jawans,* the Personnel Below Officer Rank (PBOR). Then we made improvement in the pension scheme. But that was after the presentation of the Budget. So, these types of expenses were unanticipated. Those things which were unanticipated we have indicated here.

I think I have covered most of the points raised by the hon. Members. On some of the important suggestions, which you have made, I would not like to respond right now. But, surely, I would like to incorporate some of them in the Budget Speech. When the Budget proposals will be unfurled to you, you yourself will come to know which of your suggestions I am accepting. This is the normal practice adopted by a Finance Minister and every time he does it.

Shri Amar has raised two important points. On one general point, I agree with him. I think everybody should agree with us that we should show a little bit restraint on believing whatever

appears in the print media or in the electronic media, and we need not indulge in character assassination through the media. Whatever deficiency it may have, we don't have any other alternative forum. The court is there. Whoever is found guilty in the court, he should be treated as guilty. But prior to that, there should not be a trial by the media and, at least, Parliament need not necessarily be agitating on media trial. This is a good point. I think it would be helpful to us if we can try to follow it.

The issue of the WTO has been raised by a number of hon. Members. But this is one of the areas where we are adhering to our interests. We are not going to give concession to Non-Agricultural Market Access (NAMA), which is in the vocabulary of WTO, unless our concerns on agriculture are addressed and the high subsidy, which the industrialised developed countries are giving to their farmers, is reduced. We are not going to give them access to NAMA. That is the reason why the DOHA Round of talks has not proceeded further. Therefore, it is not correct to say that our farmers are having these problems because of the WTO. Farmers have problems. There is no doubt about it. What we have done is this. In the last four or five years, you just see how much Minimum Support Price we have increased.

Price is an important issue. If I do not respond to price, everybody will say that he has escaped it. But, is it not a fact that one of the reasons of rise in prices of essential commodities is the cost-push element? If I determine the price of one quintal of sugarcane at Rs.200 with 8.5 per cent recovery, then, you yourself can calculate and come out with what would be the price of one kilogram of sugar. We determine the procurement price of one quintal. The Government is going in for substantial procurement, to the extent of 30 to 33 per cent of the total production and is determining the benchmark and the prices. Now, it is Rs.1000 per quintal on which we procure. If we procure at Rs.950+Rs.50 bonus, that is, Rs.1000 per quintal, then, what would be the price of one kilogram of rice? Therefore, there is a cost-push element. Nobody is denying that it is causing sufferings to the people, particularly disorganised and weaker sections of the people. How to address this issue? Addressing this issue is not that you would not enhance the procurement price. Procurement prices have to be enhanced and farmers have to be encouraged. Farmers are to be given more and more remunerative prices so that they have the incentive of producing more and, at the same time, help in a situation where there is a shortfall. In respect of pulses, there is a shortfall. The other day, while intervening in the debate, I pointed out that even in early 1990s, we tried with our agricultural scientists to make a breakthrough in the production of pulses that could not prove successful. So, pulses are in short supply of more than four million tonnes and very few countries produce pulses like Turkey, Myanmar, Argentina and some other countries. And, we are importing. If you simply apply your common sense, you will find out the answer that if the international prices were not higher, our traders would have

easily imported. The Government is importing. Forget about the Government's inefficiency, the so-called inefficiency of the public sector, why the private traders are not importing? There is no duty. It is under OGL. There is no forward trading. These are banned items in forward trading. Therefore, these are the issues which are pushing up the prices. But, we shall have to address it. It is not to pass on the blame. It is just to accept the ground reality. Shri Mohammed Amin was suggesting that all the things should be distributed through Public Distribution System. Fine! Ideologically and theoretically, it sounds nice. But, we are not able to distribute only 10 to 14 items through PDS. Not a single State Government is in a position to do that. No Central Government can do it, to carry on with PDS in 6,00,000 villages and a few thousand towns. It is primarily the responsibility of the State Governments and they will have to do it. We can assist them. We can provide them the materials. Yesterday, I had the meeting of the Empowered Group of Ministers on Food Items. Food prices are going up. But, the offtake, which we are providing to the States, is much less. When we are offering them in terms of 1000 tonnes, they are picking up in terms of 100 tonnes. Therefore, these issues are to be addressed and it is not to pass on the responsibility or the buck. We shall have to do it collectively and we are doing it. But, I, myself, have expressed my concern that the prices are a major area of concern and we shall have to address it. We are doing it. Nobody has said that it is not a matter of concern. Nobody says that price is all right. It is not all right because convergence between WPI and CPI is not taking place for a very long period of time. But, we cannot merely solve these issues by indulging in rhetoric. For that, corrective economic steps have to be taken and I can assure the hon. Members that whatever steps are needed, we will take those steps.

And I am quite confident that Indian economy has started recovering and it will recover because we have the resilience and we have confidence in our workers, in our farmers and in the people of this country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

The Jharkhand Appropriation (No. 3) Bill, 2009

And

The Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill, 2009

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I move:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand for the services of the financial year 2009-10, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

That the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, the 2009-10 Budget of the State of Jharkhand received the assent of the President on 22nd July, 2009 and the date of the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2009 is 20th October, 2009. The matter for consideration, today, is the Supplementary Budget for 2009-10 and the Bill to amend the Jharkhand Contingency Fund Act, 2001. The Jharkhand Supplementary Budget amounting to Rs.1,074.03 crores provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the moneys required to meet the supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Jharkhand and the grants made by the Lok Sabha for expenditure of the Government of Jharkhand for the financial year 2009-10.

Let me also brief the hon. Members about the background of the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Bill. Since the Parliament was not in session and circumstances existed, which rendered it necessary for temporary enhancement of the ceiling of the Jharkhand Contingency Fund from Rs.150 crores to Rs.500 crores for the financial year 2009-10 to carry out drought relief works in the State which has affected all the 24 districts of the State. The Cabinet had recommended to the President to promulgate the Jharkhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2009 on the 20th October, 2009.

The questions were proposed.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : उपसभापति जी, झारखंड सरकार की जो पूरक अनुदान मांगों की और Contingency Fund रिलेटिड बात माननीय मंत्री जी ने उठाई है और यह कहा है कि इस राशि को डेढ़ सौ करोड़ से बढ़ाकर पांच सौ करोड़ कर दिया जाए। माननीय उपसभापति जी, मैं कुछ दुविधा में हूं कि इस पर क्या बोला जाए। चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है और 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा।